● वर्ष-5

● अंक-219

रायपुर, गुरुवार
30 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› आईपीएस संतोष सिंह ने संभाला...

दूसरे चरण में रिकार्ड 92% मतदान

चुनाव बाद भी सीएपीएफ की 700 कंपनियां बंगाल में ही रहेंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आज 142 सीटों पर मतदान कराए गए। बंगाल की जनता ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दूसरे चरण में 1,448 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। कुछ जगहों से टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें भी आईं। शाम पांच बजे तक 89.99 फीसदी मतदान हुआ। अब अंतिम घंटे में कतार में लगे मतदाता मतदान कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से आंकड़े जारी किए जाने के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत में बदलाव हो सकता है। अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग से मतदान की पल-पल की अपडेट के लिए जुड़ें...

जिलों के नाम	1 बजे तक	3 बजे तक	5 बजे तक
हुगली	64.57	80.77	90.34
हावड़ा	60.68	77.73	89.44
कोलकाता उत्तर	60.18	78.00	87.77
कोलकाता दक्षिण	57.73	75.38	86.11
नादिया	61.41	79.79	90.28
उत्तर 24 परगना	59.20	77.39	89.74
पूर्वा वर्धमान	66.80	83.11	92.46
दक्षिण 24 परगना	58.58	76.75	89.57

मतदान के बाद बवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही उत्तर 24 परगना के अरबिंद रैल इलाके में भारी हिंसा भड़क गई। यहां बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हिंसा की सूचना मिलते ही भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है।

नोआपाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने मतदान के अंतिम घंटों में गंभीर धांधली का आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह के अनुसार, एक स्थानीय पार्षद के पति ने फर्जी तरीके से चार बूथों के कार्ड बनवा लिए हैं और वह जबरन मतदान केंद्रों में घुसकर वोट डाल रहा है। सिंह ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद पीठासीन अधिकारी सब कुछ देखकर भी चुप हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। भाजपा नेता ने दावा किया कि उनके समर्थकों को डराया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके।

पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद भी राज्य में सुरक्षा चाक-चौबंद रहेगी। चुनाव आयोग की तैनाती योजना के अनुसार, आज पोलिंग खत्म होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 700 कंपनियां राज्य में ही रुकी रहेंगी। ये कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी संभालेंगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक ये बल बंगाल में तैनात रहेंगे ताकि चुनावी नतीजों से पहले और बाद में किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी को रोका जा सके। यह फैसला राज्य के संवेदनशील माहौल को देखते हुए लिया गया है।

मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने अपनी जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फेसबुक के जरिए दावा किया कि उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार भाजपा बंगाल में हार की कगार पर है। ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में दो-तिहाई बहुमत के साथ फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। मतदान के बीच आए मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता का भरोसा एक बार फिर टीएमसी के साथ है।

पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान पूर्व वर्धमान जिले के बिरुरी प्राथमिक विद्यालय के पास बम मिलने से हड़कंप मच गया। मतदान केंद्र के पास बम की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और एनआईए, सीआईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

एग्जिट पोल : बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद

बंगाल में बीजेपी का फैक्टर फिट, 4 में भाजपा को बहुमत 2 में दीदी का जादू

कोलकाता। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले राजग तथा तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता बरकरार रहने , केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की एक दशक बाद स्पष्ट जीत जबकि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मामूली बढत के साथ जीत का अनुमान व्यक्त किया गया है।

असम विधानसभा की कुल 126 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की सत्ता के बरकरार रहने के स्पष्ट अनुमान व्यक्त किये गये हैं।एक्सिस माई इंडिया ने असम में राजग को 88 से 100 सीट, कांग्रेस प्लस को 24 से 36 और अन्य को 0 से तीन सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। मेट्रिज ने राजग को 85 से 95, कांग्रेस प्लस को 25 से 32 सीट और अन्य को छह से 12 सीट मिलने की बात कही है।चाणक्य स्ट्रेटजी ने राजग को 88 से 98 , कांग्रेस प्लस को 22 से 32 और अन्य को तीन से पांच सीटें दी हैं।

वहीं वोट वाइब्स ने राजग को 90 से 100 , कांग्रेस प्लस को 23 से 33 , और अन्य को शून्य से छह सीट दी हैं।केरल में एग्जिट पोल में दस वर्ष बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सत्ता में वापसी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।एक्सिस माई इंडिया ने 140 सीटों वाली विधानसभा में यूडीएफ को 78 से 90, सत्तारूढ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को 49 से 62 और राजग को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।

सीएनएन न्यूज 18 ने यूडीएफ को 70 से 80, एलडीएफ को 56 से 68 और राजग को 0 से 4 जबकि मेट्रिज ने यूडीएफ को 70 से 75 , एलडीएफ को 60 से 65 और राजग को 3 से 5 सीट मिलने की बात कही है।पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच कांटे की तथा रोमांचक टक्कर के बीच भाजपा को मामूली बढत के साथ जीतने का अनुमान व्यक्त किया गया है।पीपुल्स पल्स ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187, भाजपा को 95 से 110 तो कांग्रेस को एक से तीन और वाम दलों को शून्य से एक सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।वहीं पोल डेयरी ने भाजपा को 142 से 171, तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने की बात कही हैमैट्रिज न्यूज ने भाजपा को 146 से 161, तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।इसके अलावा एबीपी ने भी भाजपा को 146 से 161, तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 और अन्य को 6 से 10 सीट मिलने की बात कही है।चाणक्य स्ट्रेटजी ने भाजपा को 150 से 160 जबकि तृणमूल को 130 से 140 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।तमिलनाडु में सत्तारूढ द्रमुक की वापसी का अनुमान एग्जिट पोल में व्यक्त किया गया है।

सीएनएन न्यूज 18 ने राज्य विधानसभा की 234 सीटों में से अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को 114 से 124 ,द्रमुक को 103 से 113 और टीवीके को 4 से 10 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।वहीं मेट्रिज ने द्रमुक को 122 से 132 , अन्नाद्रमुक को 87 से 100 और टीवीके को 65 से 80 सीट मिलने की बात कही है।पीपुलस् पल्स ने द्रमुक को 125 से 145 , अन्नाद्रमुक को 65 से 80 और टीवीके को 18 से 24 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।

एक्सिस माई इंडिया ने अन्नाद्रमुक को 22 से 32 द्रमुक को 92 से 110 जबकि टीवीके को 98 से 120 सीटें दी हैं। पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा में भी राजग की सत्ता में वापसी का अनुमान व्यक्त किया गया है। एक्सिस माई इंडिया ने राजग को 16 से 20, कांग्रेस प्लस को छह से आठ और टीवीके को दो से चार सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है।पीपुल्स पल्स ने राजग को 16 से 19 , कांग्रेस प्लस को छह से आठ सीटें दी हैं जबकि सी वोटर ने राजग और कांग्रेस को 13 से 17 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है।

एक अन्य एजेन्सी प्रजा पोल ने राजग को 19 से 25 और कांग्रेस को छह से 10 सीट तथा टीवीके को शून्य सीटें दी हैं

तृणमूल को बढ़त देने वाले सर्वे

वहीं कुछ एजेंसियों ने तृणमूल कांग्रेस की वापसी का दावा किया है। पीपल्स पल्स के सर्वे में तृणमूल को 178 से 189 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा 95 से 110 सीटों के बीच रह सकती है।जनमत पोल्स के अनुसार तृणमूल कांग्रेस 195 से 205 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रख सकती है। भाजपा को 80 से 90 सीटें मिलने की संभावना है। जेवीसी के सर्वे में मुकाबला बेहद करीबी बताया गया है, जिसमें तृणमूल को 131 से 152 सीटें और भाजपा को 138 से 159 सीटें मिल सकती हैं।

बुधवार को राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 7 जिलों की 142 सीटों पर वोटिंग हुई।

कालाहांडी में 4.1 तीव्रता का भूकंप, गरियाबंद में भी महसूस हुए झटके

गरियाबंद। ओडिशा के कालाहांडी जिले में बुधवार शाम आए 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले गरियाबंद तक महसूस किए गए, जिससे पूरे इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र कालाहांडी जिला रहा और इसकी गहराई लगभग 24 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप के झटके शाम करीब 7:42 बजे महसूस किए गए, जो लगभग 3 सेकेंड तक रहे। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में लोगों ने तेज कंपन के साथ हल्की

गड़गड़ाहट जैसी आवाज भी महसूस की। अचानक हुए इस झटके से लोग घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि भूकंप की तीव्रता मध्यम होने के कारण किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार देवभोग क्षेत्र में उस समय मौसम भी बदल रहा था। बारिश के बाद आसमान में बिजली चमक रही थी, इसी दौरान अचानक जमीन में कंपन महसूस हुआ।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास को लेकर व्यापक चर्चा की गई और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर, जो भौगोलिक रूप से केरल से भी बड़ा क्षेत्र है, दशकों तक विकास से वंचित रहा, लेकिन अब वहां योजनाओं का तीव्र विस्तार हो रहा है और विकास की नई धारा स्थापित हो रही है।

प्रमुख समाचार

राजनाथ ने पाकिस्तान को दी क्लीन चिट : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है और दावा किया कि ऐसा अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि निश्चित रूप से रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति और निर्देश पर ही किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में क्लीन चिट दी है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और सवाल किया कि सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केन्द्र नहीं है।उन्होंने सवाल किया क्या वहां भारत के खिलाफ आतंकी शिविर नहीं चल रहे हैं और क्या मुंबई तथा पहलगाम जैसे हमलों की साजिश पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने नहीं रची थी। श्री रमेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रति सरकार का यह रुख अमेरिका को खुश करने और चीन के सामने संतुलन साधने की नीति का हिस्सा है। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को लेकर दिए गए श्री मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि श्री सिंह का यह भी उसी तरह का चौंकाने वाला रुख है।

एक्सिट पोल : असम में तीसरी बार भाजपा सरकार

नईदिल्ली। 2026 विधानसभा चुनावों के नवीनतम एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए असम में आराम से बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने के लिए तैयार है। यह पोल सत्तारूढ़ गठबंधन को सीटों और वोट शेयर दोनों में निर्णायक बढ़त का अनुमान लगाता है। 126 विधानसभा सीटों में से, एनडीए को 88 से 100 सीटें जीतने की उम्मीद है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। अकेले भाजपा को 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में उसके प्रभुत्व को फिर से स्थापित करता है। इसके सहयोगी दल - असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) - संभवत: 16 से 20 सीटें और जीतेंगे, जिससे गठबंधन की कुल सीटों की संख्या में मजबूती आएगी। एग्जिट पोल मतदान केंद्रों से बाहर निकल चुके लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। एग्जिट पोल का उद्देश्य मतदाताओं के मूड का अनुमान लगाना होता है, लेकिन ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं। तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन (कॉन्ग+) को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, जो दर्शाता है कि विपक्ष की स्थिति में मामूली सुधार होने के बावजूद, वह एनडीए को कड़ी

हेट स्पीच पर अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता नहीं

नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने देश भर में नफरती भाषण (हेट स्पीच) पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी नया दिशा-निर्देश जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच की समस्या से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। मौजूदा कानूनी ढांचे में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त तंत्र है। न्यायालय ने कहा कि असली चिंता कानून का अभाव नहीं, बल्कि उसे लागू करने को लेकर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत वैधानिक योजना आपराधिक कानून को गति में लाने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया प्रदान करती है।पीठ ने कहा कि इसका उपचार कई स्तरों पर उपलब्ध हैं। अगर पुलिस उच्चतम न्यायालय के 12 नवंबर, 2013 के %ललिता कुमारी% फैसले के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने में नाकाम रहती है, तो पीड़ित व्यक्ति वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगा सकता है।

ग्रेट निकोबार में विकास नहीं, विनाश हो रहा है: राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली की ग्रेट निकोबार में चल रही 81,000 करोड़ रुपये की सबसे महत्वाकांक्षी रणनीतिक अवसंरचना परियोजना पर निशाना साधते हुए इसे हमारे जीवनकाल में देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे जघन्य अपराधों में से एक बताया। कांग्रेस नेता, जो वर्तमान में द्वीप का दौरा कर रहे हैं, ने कहा कि केंद्र की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विकास की आड़ में विनाश के अलावा कुछ नहीं है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सरकार इसे परियोजना कहती है। मैंने जो देखा है, वह कोई परियोजना नहीं है। यह लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है। यह 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन है जिसे नष्ट होने के लिए अभिशप्त किया गया है। यह उन समुदायों को नजरअंदाज किया गया है जिनके घर छीन लिए गए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप के जंगलों के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वहां के पेड़ याद से भी पुराने हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जंगल पीढ़ियों से पोषित हुए हैं।

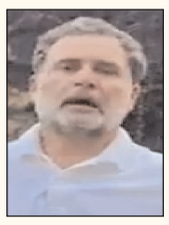

आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ाई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। आसाराम की जमानत अवधि 6 मई को खत्म हो रही थी। आसाराम ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने बुधवार को आसाराम की जमानत अवधि को 25 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए उनके वकील यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि आसाराम का इलाज अभी जारी है। ऐसे में इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 29 अक्टूबर 2025 को जमानत दी थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था।

राजनीतिक सफर के 25 साल : सत्ता की सवारी करना जानते हैं मोदी

सनत जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से सत्ता को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, दिखला दिया। सत्ता और नौकरशाही पर मोदी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए, 2001 से लेकर 2026 तक का जो राजनीतिक सफर पूरा किया है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है, भारत में उनके मुकाबले का कोई ऐसा राजनेता नहीं देखने में आया जिसने सत्ता की सवारी इस तरह से की हो। इसके पहले स्वतंत्र भारत में कोई नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विषम परिस्थितियों में सत्ता के उन सभी घोडों को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की, जिनको नियंत्रित करना आमतौर पर उसके पहले के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं हुआ। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद गोधरा कांड हुआ था। जिसमें उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को कहना पड़ा था, मोदी जी राज धर्म का पालन करें। उस विषम परिस्थितियों से नरेंद्र मोदी अपने आपको बाहर निकलने में सफल रहे। 2002 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। गुजरात में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केशू भाई पटेल और शंकर सिंह बघेला को घर बिठाकर अपनी ताकत का एहसास कराया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए संघीय और केंद्रीय व्यवस्था को कब कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह उन्होंने गुजरात से जाना। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप यह भी जाना कि किस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं का कैसे उपयोग करना है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, पार्टी संगठन और विपक्षी दलों के नेताओं को किस तरह से काबू करना है, या अपने पाले में लाना है। यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू करके विपक्ष को एक ही झटके में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। काला धन तो वापस नहीं आया। नोटबंदी के कारण उन्होंने उस

दौरान के अधिकांश राज्यों के चुनाव और लोकसभा जीत लिया। विपक्ष को पैसे-पैसे के लिए तरसा दिया। समय बीता, अब कोई भी आदमी नोटबंदी लागू होने के बाद काला धन और आतंकवाद खत्म होने की बात नहीं करता है। कुछ इसी तरह से उन्होंने जीएसटी कानून लागू किया। उसका उत्सव मनाया। देखते ही देखते राज्यों और केंद्र के राजस्व में कई गुना इजाफा कर लिया। आम जनता के ऊपर भारी टैक्स लगा, लेकिन जनता ने ताली बजाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने जो भी निर्णय लिए उसका कितना भी विरोध हो, उन्होंने बिना डरे उसका मुकाबला जिस तरह से किया, यह नरेंद्र मोदी से अच्छा और कोई नहीं जानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर राजनीति करती थी। उस विचारधारा के विपरीत लोगों को जिस तरह से उन्होंने भाजपा में शामिल किया। सत्ता में उन्हें भागीदार बनाया। कई राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें बनाईं। गुजरात और दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से नौकरशाही और न्यायपालिका के साथ बिना टकराव उन पर सवारी करने में सफलता हासिल की। जांच एजेंसियों का उपयोग उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने, विपक्षियों को समाप्त करने, में जिस तरह से किया है। आज उसकी प्रशंसा सारी दुनिया में हो रही है। भाजपा संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो पकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान में है। इसके पहले कभी किसी भी संगठन प्रमुख की ऐसी पकड़ जनसंघ, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मे देखने को नहीं मिली। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जिनके पास लोकसभा में दो तिहाई बहुमत था, वह भी जो ताकत हासिल नहीं कर पाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ताकत का एहसास सारे देश को करा दिया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के अनुकूल काम करती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जो टकराव न्यायपालिका और कार्यपालिका का केंद्रीय सत्ता के साथ होता था अब लोग उसे भूल चुके हैं। अब वही होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका उनके इशारे पर काम करती है। मंत्रिमंडल पर उनका एकाधिकार है। पार्टी संगठन में एकाधिकार है।

ट्रैक्टर चलाने व मरम्मत सीख रहे 40 आत्मसमर्पित नक्सली

नारायणपुर। जिले के लाइवलीहुड कॉलेज स्थित पुनर्वास केंद्र में हिंसा और आतंक का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों को केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आधार भी मिल रहा है। कभी बंदूक थामने वाले इन हाथों ने अब खेतों की खुशहाली के लिए ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामना शुरू कर दिया है। पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के समक्ष 40 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने ट्रैक्टर चलाने और उसकी मरम्मत सीखने की इच्छा जताई। कलेक्टर ने इस सकारात्मक पहल को तुरंत मंजूरी दी और आज बुधवार से प्रशिक्षण कार्यक्रम का श्रीगणेश कर दिया। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देख-रेख में ये सभी लोग अब ट्रैक्टर की तकनीकी बारीकियों और रख-रखाव का प्रशिक्षण ले रहे हैं। गौरतलब है कि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में साइकिल तक नहीं चलाई थी, लेकिन आज वे पूरी गंभीरता के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों का कौशल सीख रहे हैं। यह प्रशिक्षण केवल कौशल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन को नई दिशा देने वाला माध्यम है। खेती-किसानी और परिवहन के क्षेत्र में इस कौशल से उन्हें न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे। अतीत की अस्थिरता और डर के साये से निकलकर अब इन लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति स्पष्ट उम्मीदें देखी जा सकती हैं। नारायणपुर का यह केंद्र आज केवल एक पुनर्वास स्थल नहीं, बल्कि विश्वास और बदलाव का एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरा है। यह साबित करता है कि सही अवसर और सहयोग मिले, तो भटका हुआ हर व्यक्ति समाज की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। प्रशासनिक पहल के तहत पुनर्वासितों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में 8 पुनर्वासितों को वोटर आईडी कार्ड वितरित किए गए, जिससे वे अब लोकतंत्र का हिस्सा बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, 40 लोगों के फॉर्म-6 भरवाकर उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह कदम उन्हें केवल पहचान ही नहीं, बल्कि समाज में बराबरी का हक भी दिला रहा है।

रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का शुभारंभ

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंडल के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं 01 पर ठंडे पेय पदार्थों हेतु ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया है। यह पहल रेलवे की यात्री-केंद्रित एवं तकनीक-आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के माध्यम से अब यात्रियों को ठंडे पेय पदार्थ खरीदने के लिए स्टॉल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री स्वयं इस मशीन का उपयोग कर अपनी सुविधा अनुसार कोका-कोला ब्रांड के विभिन्न ठंडे पेय पदार्थ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मशीन का उपयोग अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक है। यात्री को सबसे पहले मशीन पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, जिसके पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से वे अपनी पसंद का पेय पदार्थ चयन कर सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित उत्पाद मशीन के नीचे स्थित डिस्पेंस बॉक्स से स्वतः प्राप्त हो जाता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दैनिक एवं लंबी दूरी के यात्रियों को समान रूप से लाभ मिलेगा। इस पहल से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने के साथ ही चिल्हर और ओवर चार्जिंग की समस्या भी दूर होगी।

भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रवण कुमार का हुआ निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक

रायगढ़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं समर्पित कार्यकर्ता श्रवण कुमार प्रधान का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे ग्राम पडिग़ांव में शोक की लहर है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस दुखद समाचार पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रवण कुमार प्रधान संगठन के एक सक्रिय, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि श्रवण कुमार प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्य किए, वे संगठन की मजबूती में महत्वपूर्ण रहे। उनकी सक्रियता और समर्पण ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई थी। वे न केवल एक कार्यकर्ता, बल्कि संगठन के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। मुख्यमंत्री ने इसे संगठन और समाज दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पित और कर्मठ व्यक्तित्व का जाना निश्चित रूप से सभी के लिए गहरा आघात है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्राप्त हो।

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार द्वारा जारी की गई अधिसूचन के अनुसार इस वर्ष उच्च न्यायालय में 18 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा चूंकि 13 और 14 जून को शनिवार रविवार होने की वजह से कोर्ट 15 जून से नियमित रूप से कार्य करेगी अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है, जो सुबह 10ः30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही करेंगे और जरूरत पडऩे पर समय बढ़ाया भी जा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट से जुड़े मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी, जबकि जरूरी मामलों के लिए अलग से आवेदन देना होगा। जमानत मामलों में अलग से अर्जेंट हियरिंग आवेदन की जरूरत नहीं होगी और उन्हें स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा। अन्य लंबित मामलों की सुनवाई के लिए अर्जेंट आवेदन अनिवार्य रहेगा। इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश में बंद रहेगा। कोर्ट ने यह भी तय किया है कि वेकेशन जज 19, 21, 26 और 28 मई और 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को सुनवाई करेंगे। वहीं जो मामले तय समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगली तारीख पर अलग सूची में शामिल किया जाएगा।

जर्जर पानी टंकी भरभराकर गिरी

■ गौरेला नगर पालिका में बड़ा हादसा टल गया. पतेरा टोला में जर्जर पानी टंकी भरभराकर गिर गई.गनीमत रही कि मौके पर कोई नहीं था.

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पतेरा टोला, वार्ड क्रमांक 1 में एक बड़ा हादसा टल गया। जब वर्षों से जर्जर पानी टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई। टंकी गिरते ही उसमें भरा हजारों लीटर पानी तेजी से बह निकला, जो आसपास के घरों में जा घुसा। पानी कई लोगों के आंगन तक पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, संबंधित पानी की टंकी पिछले करीब 10 साल से बंद पड़ी थी और इसकी हालत बेहद खराब थी। स्थानीय रहवासियों ने कई बार नगर पालिका प्रशासन को टंकी की जर्जर स्थिति से अवगत कराते हुए इसे चालू न करने की मांग की थी। इसके बावजूद पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने टंकी में दोबारा पानी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही टंकी में पानी का दबाव बढ़ा, वह अचानक भरभरा कर गिर गई।गनीमत रही कि हादसे के समय टंकी के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, पानी के तेज बहाव से लोगों के घरों में पानी घुस गया और कुछ सामान भी प्रभावित हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। रहवासियों ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बार-बार की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। लोगों का कहना है कि यदि पहले ही टंकी की मरम्मत या हटाने की कार्रवाई की जाती, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिलहाल, घटना के बाद प्रशासन मौके का निरीक्षण कर रहा है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।

धड़ल्ले से चल रहा अवैध प्लाटिंग का बड़ा खेल, 32 टुकड़ों में बंटी जमीन

महासमुंद। जिले में अवैध प्लाटिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक ढिलाई और विभागों के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाकर जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेच दिया गया। इस पूरे खेल में आम लोगों की जीवनभर की कमाई दांव पर लग गई है। केन्द्रीय विद्यालय के पास स्थित रमनटोला इलाके में वर्ष 2019 से अवैध कॉलोनी का निर्माण जारी है। यहां चेतना मालू (पति संजय मालू) के नाम दर्ज खसरा नंबर 1800 की 2 एकड़ जमीन को डायवर्सन कराकर करीब 32 हिस्सों में बांटकर बेच दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से लेआउट की स्वीकृति नहीं ली गई। इस अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में सड़क, पानी, नाली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। चूंकि कॉलोनी का विकास तय नियमों के तहत नहीं हुआ, ऐसे में कॉलोनाइजर की कोई जवाबदेही तय नहीं होती और परेशानी सीधे खरीदारों को झेलनी पड़ती है। जांच में सामने आया है कि अवैध प्लाटिंग की शुरुआत राजस्व विभाग से होती है। बड़े भू-भाग का डायवर्सन बिना पर्याप्त जांच के कर दिया जाता है। इसके बाद भूमि उपयोग प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं होती और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से समन्वय भी नहीं किया जाता। इसी खामी का फायदा उठाकर जमीन को छोटे प्लॉट्स में काटकर ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तक जमीन से जुड़ी अहम जानकारी समय पर नहीं पहुंचती। वहीं नगर पालिका भी अधिकतर मामलों में शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई करती है। यही वजह है कि शहर के करीब 30 वार्डों में अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। हाल ही में रायपुर रोड पर कार्रवाई हुई, लेकिन रमनटोला में वर्षों से चल रहे इस मामले पर ध्यान नहीं गया। खसरा नंबर 1800 की जमीन को कई हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों को बेचा गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रमुख खरीदारों में शिव कुमार चंद्राकर, कुलेश कुमार दीवान, शंकरदास मानिकपुरी, नरेश कुमार कंवर, मीना साहू, श्रद्धा पाण्डेय, अनिता देवांगन, चिंतामणी पटेल, लता साहू, रेखा साहू, मेहत्तरू देवांगन, अवंतिका मन्नाडे, लक्ष्मी धीवर, शशी गिरी गोस्वामी, राकेश कुमार यादव, सुमित जैन और अंशुल जैन शामिल हैं। कुल मिलाकर यह जमीन करीब 32 टुकड़ों में बेची गई है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक संजू लाल सिंह का कहना है कि जमीन के डायवर्सन की जानकारी विभाग को समय पर नहीं मिलती, जबकि निवेश क्षेत्र में यह अनिवार्य है। जानकारी के अभाव में लोग बिना पूरी जांच के जमीन खरीद लेते हैं, जिससे बाद में परेशानी होती है। गौरतलब है कि कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए, जैसे कॉलोनाइजर का पंजीयन, जमीन के स्वामित्व के कागजात, स्वीकृत लेआउट, नगर पालिका की अनुमति, डायवर्सन प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़

नाली में पेशाब करने को लेकर हुआ विवाद चाकूबाजी तक पहुंचा

बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में नाली में पेशाब करने की बात को लेकर हुआ विवाद जानलेवा हमले तक पहुंचा। इस मामले में करीब 10 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों और 7 अपचारी बालकों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी सनत सारथी ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अप्रैल की रात करीब 12 बजे वह खाना खाने के बाद प्रभात चौक चिंगराजपारा में टहल रहा था। इसी दौरान विक्की अहिरवार और उसके साथियों ने नाली में पेशाब करने की बात पर विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया। इसके बाद डंडे और चाकू से भी वार किया गया। इस हमले में सनत सारथी के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई है। बीच-बचाव करने पहुंचे रेखा सारथी, बिट्टू विश्वकर्मा, सोनी सिंह ठाकुर और तिलक दास मानिकपुरी को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की।

महिला द्वारा ज्वेलर्स संचालक पर मारपीट का आरोप

दुर्ग। सहेली ज्वेलर्स के संचालक पर महिला ने बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उन्हें गहने खरीदने थे। इसके लिए वो सहेली ज्वेलर्स पहुंची।जहां एडवांस के तौर पर महिला ने 50 हजार रुपए जमा कर दिए।ये एडवांस रकम महिला ने सोने के कंगन समेत चार गहनों के लिए जमा की थी। महिला का आरोप है कि वो एडवांस रकम की रसीद लेकर जब घर पहुंची तो उसकी नजर रसीद की तारीख पर गई। जो एडवांस जमा करने की तारीख से अलग थी। इसके बाद महिला वापस ज्वेलर्स के पास पहुंची और रसीद में दर्ज तारीख को सुधारने को कहा।लेकिन ज्वेलर्स संचालक मदन जैन और भरत जैन ने महिला की रसीद सुधारने के बजाय उसके साथ बदतमीजी की। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विवाद थाने और कलेक्टर कार्यालय तक जा पहुंचा। मामले को शांत करने के बजाय ज्वेलर्स संचालकों ने डराने-धमकाने की कोशिश की। एक महिला पुलिस हवलदार को बुलाकर कथित रूप से पैसे देकर उनके साथ गाली-गलौज करवाई गई।

अंबिकापुर नगर निगम के निर्माण कार्य में बाल मजदूरी

सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम पर बाल श्रम करवाने का आरोप लगा है। निगम के निर्माण कार्य का एक वीडियो सामने आया है जहां एक नाबालिग बच्ची कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर पर कंक्रीट ढोते दिख रही है। इस दौरान वहां कई मजदूर और ठेकेदार भी नजर आए। नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि उसका एक छोटा बच्चा है। जिसे दूध पिलाना पड़ता है। इस दौरान काम बंद ना हो इसलिए वह अपनी नाबालिग बच्ची को काम पर लगाती है। बाल श्रम का मामला सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाल अधिकारों के संरक्षण के जानकार ने इस घटना की निंदा की है। सामजिक कार्यकर्ता एएन पाण्डेय ने आरोप लगाया कि अंबिकापुर नगर निगम के लिए नियम कानून कुछ भी मायने नहीं रखता। यहां माफिया लोगों का राज है और निगम के अधिकारी-कर्मचारी माफिया के बंधुआ मजदूर हैं। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण अधिनियम के अननुसार नाबालिग बच्चों से काम करवाना बहुत बड़ा अपराध है इस पर जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।

ड्रग्स नेटवर्क के मुख्य आरोपी आकाश ठाकुर गिरफ्तार

बीजापुर। बस्तर के बीजापुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ है। ड्रग्स नेटवर्क के मुख्य आरोपी आकाश ठाकुर को पुलिस ने दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महीने से फरार चल रहा था। जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आकाश ठाकुर कार वॉश सेंटर की आड़ में सूखे नशे का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उक्त कारवॉश सेंटर से गोली, कैप्सूल और थिनर जैसी नशे की सामग्री बरामद की थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई थी। इस प्रकरण में आरोपी के सहयोगी धर्मेन्द्र कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेजा जा चुका है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दंतेवाड़ा में दबिश दी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य सहयोगियों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है।

बच्चा चोरी की अफवाह ग्रामीणों ने फेरीवालों को पीटा

जगदलपुर। जिले के लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र अंर्तगत बाजारपारा में बीती रात कुछ ग्रामीणों ने मध्यप्रदेश से सामान बेचने आये लोगों पर बच्चा चोरी करने का शक जताते हुए बवाल मचा दिया। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग आ पहुंचे। जहां फेरी वालों के साथ मारपीट के साथ ही गाली गलौज भी की गई। डर के चलते फेरीवालों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इसकी सूचना लोहंडीगुड़ा थाना को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पंहुचकर फेरीवालों को अपने साथ थाने ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश जिले के सीहोर गांव में रहने वाले परिवार के लोग फेरी का सामान बेचने के लिए 2 दिन पहले लोहंडीगुड़ा पहुंचे। जहां एक किराये के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। बीती रात को उनके घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन फेरी वालों के साथ आये कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर कुछ बच्चे भाग गए तो वहीं एक बच्चा जाने का नाम नहीं ले रहा था।

नौकरी दिलाने के नाम पर पोस्ट ऑफिस का फर्जी आदेश वायरल

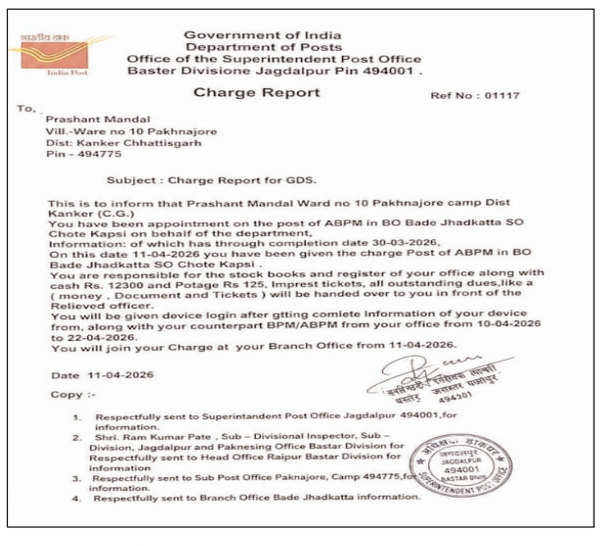

Government of India
Department of Posts
Office of the Superintendent Post Office
Baster Divisione Jagdalpur Pin 494001 .

Charge Report Ref No : 01117

To,
Prashant Mandal
Vill.-Ware no 10 Pakhnajore
Dist: Kanker Chhattisgarh
Pin - 494775

Subject : Charge Report for GDS.

This is to inform that Prashant Mandal Ward no 10 Pakhnajore camp Dist Kanker (C.G.)
You have been appointment on the post of ABPM in BO Bade Jhadkatta SO Chote Kapsi on behalf of the department.
Information: of which has through completion date 30-03-2026.
On this date 11-04-2026 you have been given the charge Post of ABPM in BO Bade Jhadkatta SO Chote Kapsi .
You are responsible for the stock books and register of your office along with cash Rs. 12300 and Potage Rs 125, Imprest tickets, all outstanding dues,like a (money , Document and Tickets) will be handed over to you in front of the Relieved officer.
You will be given device login after gtting comlete Information of your device from, along with your counterpart BPM/ABPM from your office from 10-04-2026 to 22-04-2026.
You will join your Charge at your Branch Office from 11-04-2026.

Date 11-04-2026

Copy :-
1. Respectfully sent to Superintandent Post Office Jagdalpur 494001,for information.
2. Shri. Ram Kumar Pate , Sub – Divisional Inspector, Sub – Division, Jagdalpur and Paknesing Office Bastar Division for Respectfully sent to Head Office Raipur Bastar Division for information
3. Respectfully sent to Sub Post Office Paknajore, Camp 494775,for information.
4. Respectfully sent to Branch Office Bade Jhadkatta information.

कांकेर। जिले के पखांजूर में इन दिनों भारतीय डाक विभाग के नाम पर जारी एक नियुक्ति आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस नकली आदेश को सच मानकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद बस्तर संभाग के डाक विभाग मुख्यालय ने इसे पूरी तरह फर्जी और धोखाधड़ी का दस्तावेज बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डाक विभाग इस प्रकरण की जांच कराएगा।

वायरल आदेश में भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, बस्तर डिवीजन जगदलपुर का नाम इस्तेमाल कर नियुक्ति आदेश जैसा दस्तावेज तैयार किया गया है। इसमें पोस्टिंग, जॉइनिंग डेट, चार्ज रिपोर्ट और अधिकारी की मुहर तक लगाई गई है, ताकि लोगों को यह असली लगे। शातिर ठगों ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर यह फर्जी पत्र थमाया और मोटी रकम वसूली। पखांजूर क्षेत्र के करीब 6 लोग इस ठगी के शिकार हुए हैं। उनसे नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। कई पीड़ितों ने पैसा देकर सामने नहीं आ रहे है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर शिकायत की तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। बस्तर डाक विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, कि किसी भी नियुक्ति पत्र, जॉइनिंग लेटर या नौकरी संबंधी दस्तावेज की पहले आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि करें। किसी दलाल, एजेंट या बिचौलिए के झांसे में आकर रकम न दें। कांकेर में वायरल यह फर्जी आदेश सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के सपनों पर डाका है।

बस्तर में मिली 1400 से ज्यादा व छत्तीसगढ़ में 7985 पांडुलिपियां

जगदलपुर। देश के संस्कृति विभाग के ज्ञानभारतम अभियान के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संग्रहण का काम किया जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के अलग जिलों में कार्य जोरों पर है। बस्तर में भी पांडुलिपियों की खोज जारी है। बस्तर में कलेक्टर व अन्य अधिकारी पांडुलिपि संग्रहकर्ताओं से संपर्ककर उनके पास सुरक्षित प्राचीन दस्तावेजों एवं पांडुलिपियों की जानकारी ले रहे हैं। पांडुलिपियों को अमूल्य धरोहर बताते हुए उनको डिजिटल रूप में संग्रह किया जा रहा है। अधिकारियों ने पुरातन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास की अमूल्य धरोहर है। बीते दिनों जगदलपुर में ओडिशा की संस्कृति से संबंधित पांडुलिपि संग्रहणकर्ता नरहरि दास और रविन्द्र दास के पास से लगभग 85 पांडुलिपियों का संग्रह पाया गया। इनमें उड़िया साहित्य में लिखित पांडुलिपि में आयुर्वेद, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां संरक्षित हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं सुरक्षित संधारण की दिशा में काम करने की बात कही है। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया कि ज्ञानभारत मिशन के अंतर्गत भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साक्ष्य पांडुलिपियां को जुटाने में टीम लगी हुई है। हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। मार्च के अंत में एक विशेष टीम का गठन नगर निगम और ग्राम पंचायत क्षेत्र में किया गया है। इसके लिए राजस्व अमले की ड्यूटी लगाई गई है। जहां से पांडुलिपियां मिलने की संभावनाएं हैं वहां टीम दस्तक दे रही है और पांडुलिपियों को संरक्षण करने में जुटी हुई है। जिनमें संस्कृति धाम, मंदिर, मठ, ट्रस्ट शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग इसे इकठ्ठा करके भी रखे हुए हैं। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे लोगों से संपर्क कर ज्ञानभारत मिशन के बारे में बताया जा रहा है। उनकी धरोहर उनके पास ही रहेगी बस इसका डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने का प्रयास है। जिससे यह पता चल सकेगा कि भारत सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध रहा ये पता चल पाएगा।मानव विज्ञान केंद्र के अधीक्षक पीयूष रंजन साहू ने बताया कि पूरे भारत के अमूल्य ज्ञान की विविधताओं और पुराने पांडुलिपियों को चिन्हांकित किया जा रहा है। जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य व्यक्ति विशेष के पास मौजूद है। 1947 के पहले की पांडुलिपियों को खोजा जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने महाविद्यालय की छात्राओं से की शैक्षणिक चर्चा

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका बुधवार को

यहां लोकभवन में संत गोविंद राम शदाणी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर की छात्राओं से रूबरू हुए। उन्होंने शैक्षणिक विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन दिया और उनके प्रश्नों का उचित समाधान किया। लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में आयोजित कार्यक्रम में श्री डेका ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। उसके बिना सफलता नहीं मिलती है। जीवन को पूर्ण करने के लिए योजना पूर्वक कार्य करना चाहिए। अच्छी योजना से जीवन भी अच्छा होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम भी करना होगा। मानवीय गुणों का होना भी आवश्यक है और शिक्षा से ही इन गुणों का विकास होता है। श्री डेका ने कहा कि अपनी खुशी अपने अंदर होती है। दूसरों से तुलना कर दुखी ना रहे बल्कि जो अपने पास उपलब्ध है उससे संतुष्ट रहिए। श्री डेका ने कहा कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने नारी की तुलना पानी से करते हुए कहा कि पानी के बिना जीवन असंभव है, उसी तरह नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती।

10वीं की टॉपर परीरानी को पूरा यकीन था टॉप टेन में जरुर आएगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के

द्वारा बुधवार को घोषित परीक्षा परिणाम में 10वीं में प्रथम स्थान हासिल करने वाली महासमुंद की परी रानी ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि उन्हें पूरा यकीन था की वे टॉप टेन में स्थान जरुर बनाऊंगी लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वे पूरे राज्य में प्रथम स्थाल हासिल करेंगी। वे 2.30 बजे से रिजल्ट आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ और टॉप टेन के प्रथम स्थान पर उनका नाम आया तो उनका और पूरे घर वालों का खुशी की ठिकाना नहीं रहा। आसपास रहने वाले लोग, सहपाठियों के साथ परिवारजन भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। इसका श्रेय वे अपने माता - पिता के साथ स्कूल के शिक्षकों को देना चाहते है।

12वीं का पेपर लीक करने वाले वेणु जंघेल पर 5 हजार का इनाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड का हिन्दी पेपर लीक करने वाले बेमेतरा जिले के बोरतरा गांव का निवासी आरोपी वेणु जंघेल (18) पर रायपुर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 130/2026 में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस ने आरोपी की सूचना देने या गिरफ्तारी कराने वाले को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेणु जंघेल (18) बेमेतरा जिले के बोरतरा गांव का निवासी है। वह वर्तमान में रायपुर के अशोक नगर गुढियारी में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ परीक्षा अधिनियम की धारा 4, 5, 10 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत मामला दर्ज है। यह मामला 14 मार्च 2026 को सामने आए परीक्षा अनियमितता और पेपर लीक केस से जुड़ा है। सेंट्रल जोन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉ. अर्चना झा ने रायपुर पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए के तहत इनाम की उद्घोषणा जारी की है। आदेश में कहा गया है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ है और उसके स्वच्छंद घूमने से समाज के लिए खतरा हो सकता है। जो व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तारी में मदद करेगा या ऐसी पुख्ता सूचना देगा, जिससे आरोपी की विधिपूर्वक गिरफ्तारी हो सके। उसे 5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनाम वितरण पर अंतिम निर्णय डिप्टी पुलिस कमिश्नर मध्य क्षेत्र का होगा।

लोक स्वास्थ्य विभाग ने तीन चिकित्सा अधिकारियों के किए तबादले

रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तीन चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए हैं जिनमें से दो को प्रभारी सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। एक को जिला अस्पताल रायपुर में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक डॉ. गायत्री कुर्रे (बांधी) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- बिलासपुर से संभागीय संयुक्त संचालक संभाग बिलासपुर, डॉ भेनुज कुमार सिन्हा शिशु रोग विशेषज्ञ शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुढियारी रायपुर से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर तथा डॉ. पुष्पेंद्र कुमार वैष्णव चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ से प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नवीन पदस्थापना की गई है।

दसवीं-बारहवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित

10वीं में 77.15 प्रतिशत और 12वीं में 83.04 प्रतिशत छात्र पास, बेटियों ने फिर मारी बाजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं में पास प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष हाईस्कूल में 77.15% और हायर सेकेंडरी में 83.04% परीक्षार्थी सफल रहे। साथ ही दोनों ही परीक्षाओं में बालिकाओं का प्रदर्शन बालकों से बेहतर रहा है।

हाईस्कूल (10वीं) का परिणाम, 77.15% छात्र पास

हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में कुल 3,21,677 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 3,16,730 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 1,40,402 बालक तथा 1,76,328 बालिकाएं शामिल थीं।

इनमें से 3,14,953 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें 2,43,016 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 77.15 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे।

बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत: 81.03%

बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत: 72.27%

श्रेणीवार परिणाम इस प्रकार है-

प्रथम श्रेणी: 1,40,108 (44.48%)
द्वितीय श्रेणी: 96,721 (30.71%)
तृतीय श्रेणी: 6,187 (1.96%)

एक या दो विषयों में 19,347 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। कुल 161 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिनमें 15 नकल प्रकरण और 143 जांच श्रेणी में शामिल हैं। वहीं 1,616 परीक्षार्थियों के आवेदन पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 परीक्षार्थियों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।

वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 76.53% था, जबकि इस वर्ष इसमें लगभग 0.62% की वृद्धि हुई है।

हायर सेकेंडरी (12वीं) का परिणाम, 83.04% छात्र सफल

हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में कुल 2,46,166 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 2,44,453 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 1,02,259 बालक तथा 1,42,194 बालिकाएं शामिल थीं।

इनमें से 2,43,898 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें 2,02,549 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 83.04 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे।

बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत: 86.04%
बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत: 78.86%

श्रेणीवार परिणाम इस प्रकार है-

प्रथम श्रेणी: 1,27,334 (52.2%)
द्वितीय श्रेणी: 72,402 (29.68%)
तृतीय श्रेणी: 2,806 (1.15%)
पास श्रेणी: 7 परीक्षार्थी

एक या दो विषयों में 23,866 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। कुल 63 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिनमें 5 नकल प्रकरण और 56 जांच श्रेणी में हैं। वहीं 492 परीक्षार्थियों के आवेदन पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 परीक्षार्थियों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 81.87त्न था, जबकि इस वर्ष इसमें लगभग 1.17त्न की वृद्धि हुई है।

रिजल्ट देखने के लिए इन लिंक पर करें क्लिक-

https://cg.results.nic.in
https://cgbse.nic.in
https://results.cg.nic.in
https://results.digilocker.gov.in
https://timesofindia.indiatimes.com
https://www.tv9hindi.com
https://education.indianexpress.com
https://www.jagranjosh.com
https://www.ndtv.in

पेपर लीक मामले में कांग्रेस का असली चेहरा उजागर: भाजपा

■प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड एनएसयूआई का ही सदस्य निकलने पर बोला कांग्रेस पर तीखा हमला

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने छत्तीसगढ़ में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। श्री चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदर्शन का ढोंग कर कार्रवाई की मांग कर रहा था, अब उस पूरे गोरखधंधे का सरगना उसी एनएसयूआई का ही सदस्य निकला है! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चिमनानी ने खुलासा किया कि पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। यह स्पष्ट करता है कि इन तत्वों को कांग्रेस का खुला संरक्षण प्राप्त है।

चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब पीएससी जैसे बड़े घोटाले करके नौजवानों के भविष्य को चौपट किया गया। अब सत्ता से बाहर होने के बाद भी इनकी आदतें नहीं बदली हैं। इनके नेता और कार्यकर्ता अब पेपर

लीक जैसे अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। श्री चिमनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

उन्होंने बताया कि एनएसयूआई के फरार नेता पर पुलिस ने 5हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और जल्द ही सभी दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र की कड़ी निंदा करते हुए श्री चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को युवाओं के भविष्य के साथ किए गए इस खिलवाड़ के लिए जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यदि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो प्रदेश की जनता उन्हें विलुप्त कर देगी।

पेपर लीक मामले पर सियासत

दीपक बैज ने बीजेपी कनेक्शन का लगाया आरोप, कहा- किसे बचा रही सरकार

■शिक्षा मंत्री बोले- कुछ हुआ ही नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं के रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक मामले में सियासत फिर शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक को निराधार बताया है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, पेपर लीक मामले में सरकार कन्फ्यूज है। एक तरफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं होने की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं इसमें बीजेपी नेता का कनेक्शन तो नहीं है। बता दें कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक मामले में एनएसयूआई के विरोध को लेकर कहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो किस बात का विरोध कर रहे।

दीपक बैज ने अंबिकापुर के सीतापुर में चार आदिवासी बच्चियों में से दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, थाने में

एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही। सरकार और पुलिस ऐसी घटना को रोकने में नाकाम है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में निराश्रित और वृद्धा पेंशन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वृद्धा, निराश्रित पेंशन की राशि 4 से 5 माह की नहीं दी गई है। वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन की 500 की राशि भी नहीं दी जा रही।

तहसीलदार और एसडीएम भी मेडिकल स्टोर की जांच करेंगे। इस मामले में पीसीसी चीफ ने कहा, दवा व्यापारियों पर जबरन का दबाव बनाया जा रहा। सरकार को ऐसे आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए। 20 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी खुले में हैं। इस पर दीपक बैज ने कहा, बारिश के बीच धान को बर्बाद करने खुले में छोड़ दिए हैं। 3100 रुपए में खरीदकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल में सरकार नीलाम कर रही। सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए नया तरीका निकाल लिया है।

सरकार एक मई से सुशासन तिहार मनाने जा रही। इस मामले में पीसीसी चीफ बैज ने कहा, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ढोंग रचा जा रहा है। सरकार अच्छा काम करती तो सुशासन तिहार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार लाखों आवेदन आए उसका क्या हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है।

आईपीएल खेलने कोहली की टीम 8 मई को पहुंचेगी रायपुर

रायपुर। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आसीबी) के दो मुकाबले होने वाले हैं। आरसीबी का 7 मई को लखनऊ में मैच है, इसके बाद उसके अंतिम दो मैच रायपुर में 10 और 13 मई को होने हैं। इसके लिए कोहली समेत सभी खिलाड़ी 8 मई को रायपुर पहुंच रहे हैं और वे 13 मई तक रायपुर में रुकेंगे। वहीं, रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस के सितारे 6-7 मई को रायपुर पहुंचने सकते हैं। ऐसे में रोहित समेत मुंबई की पूरी टीम के भी 4 दिन तक रुकेगी। कोलकाता के खिलाड़ी 8 मई को दिल्ली में मैच खेलने के बाद रायपुर पहुंचेंगी। हालांकि, कोलकाता के रायपुर पहुंचने की तिथि निश्चित नहीं है। इन मैचों में प्रदेश के क्रिकेट

प्रेमियों को एकबार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने पसंदीदा क्रिकेटरों का धमाल देखने को मिलेगा। इस बार आरसीबी के विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ी 6 दिनों तक रायपुर में ठहरने वाले हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। स्टेडियम की साफ-सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। सीएससीएस के मिली जानकारी के अनुसार तैयारियों का जायजा लेने के लिए आरसीबी की टीम 3 मई को रायपुर पहुंच रही है। टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। अब तक बेंगलूरु में खेले गए आरसीबी के घरेलू मैचों के टिकटों की बिक्री मैचों के एक हफ्ते पहले शुरू हुई है। ऐसे में रायपुर में होने वाले मुकाबलों के टिकटों की बिक्री 3-4 मई से शुरू होने की संभावना है। 10 और 13 मई को रायपुर में होने वाले मुकाबले में खिलाड़ियों समेत स्टेडियम के एंट्री गेट तक की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आरसीबी ने अपने हाथों में ली है।

धमतरी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल

500 विद्यार्थियों को मिलेगी सैन्य शिक्षा की राह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक मानचित्र पर धमतरी जिला जल्द ही एक नई पहचान दर्ज कराने जा रहा है। जिले में 500 सीटों की क्षमता वाले एक विशाल सैनिक स्कूल की स्थापना की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव विधिवत अनुमोदित कर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है। यह न केवल धमतरी बल्कि पूरे रायपुर संभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

प्रस्तावित सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सैन्य करियर के लिए तैयार करना है। यहाँ पढने वाले विद्यार्थियों को अनुशासित वातावरण में न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त होगी, बल्कि उनके शारीरिक एवं नेतृत्व कौशल का भी सर्वांगीण विकास हो सकेगा। यह संस्थान विशेष रूप से उन मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित होगा, जो भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह सैनिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं और विश्वस्तरीय अधोसंरचना से सुसज्जित होगा। परिसर में डिजिटल शिक्षण माध्यमों से लैसअत्याधुनिक स्मार्ट कक्षाएं होंगी। शारीरिक फिटनेस और खेलों के लिए विस्तृत मैदान के साथ-साथ सुव्यवस्थित छात्रावास सुविधा तथा समृद्ध पुस्तकालय एवं विशेष रक्षा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

धमतरी के कलेक्टर ने इस परियोजना को जिले के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस प्रोजेक्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। रक्षा मंत्रालय की टीम जल्द ही संभावित स्थलों का निरीक्षण करेगी। हम भूमि चयन से लेकर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तक, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर रहे हैं ताकि इस स्कूल को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके।

सैनिक स्कूल की स्थापना से शिक्षा के साथ-साथ क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इस संस्थान के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही, यह स्कूल धमतरी को प्रदेश के एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए एक सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। अब पूरे प्रदेश की निगाहें रक्षा मंत्रालय के आगामी निरीक्षण और स्वीकृति पर टिकी हैं, जिसके बाद निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

साय सरकार की 'रामलला दर्शन योजना' से प्रदेशवासियों को मिल रहा आध्यात्मिक संबल

■ दुर्ग संभाग के 850 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित 'रामलला दर्शन योजना' के अंतर्गत राजनांदगांव और दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आज भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। दोनों स्टेशनों से कुल 850 तीर्थयात्री भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान स्टेशन परिसर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पर्यटन मंडल और आईआरसीटीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर यात्रियों

का आत्मीय अभिनंदन किया। तिलक लगाकर, पुष्पवर्षा कर और पारंपरिक लोकनृत्य की प्रस्तुति के साथ यात्रियों को विदाई दी गई, जिससे यह यात्रा उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गई।

इस अवसर पर सांसद श्री संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दुर्ग स्टेशन पर महापौर अल्का बाघमारे और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। सभी अतिथियों ने इस योजना को साय सरकार की एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी पहल बताते हुए कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों की आस्था को सम्मान देने के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत कर रही है।

साय सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को नि:शुल्क यात्रा, भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक 45 हजार 900 श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से रामलला के दर्शन कर चुके हैं और इस यात्रा के साथ यह संख्या बढ़कर 46 हजार 750 हो जाएगी। खास बात यह है कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ-साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराए जा रहे हैं।

यात्रा पर रवाना हो रहे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालुओं ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन साय सरकार की इस योजना ने उनका यह सपना साकार कर दिया। यात्रियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए इसे आमजन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना
(प्रथम आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन.आई. टी. क्र सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाख में)
1	2	3
318/189719	SPECIAL REPAIR WORK IN KHAIRKHUT-TARPONGI-NINWA-KIRNA ROAD (MDR-196) IN KM 12/2 To 12/10 = 1.00KM UNDER PWD SUB DN. NO. 2. RAIPUR	रू. 31.79 लाख

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.05.2026 समय सायं 5.30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर मंडल क्रं.-1, रायपुर (छ.ग.)

जी-262700416/4

समाचार पचीसा
रायपुर, गुरुवार 30 अप्रैल 2026

बंगाल में मतदान बढ़ने से उलझे समीकरण

सुरेश हिंदुस्तानी

पश्चिम बंगाल में भारी मतदान से यह तो तय हो चुका है कि मतदाता चुनाव का महत्व समझ चुका है। लेकिन इससे राजनीतिक दलों को हिसाब लगाने में पसीना बहाना पड़ रहा है। सबके गणित उलझ गए हैं। पहले चरण में 92 प्रतिशत मतदान जहाँ एक ओर राजनीतिक दलों के लिए चिंता की लकीर खींच रहा है, वहीं एक राजनीतिक लाभ देने का भी संकेत करने वाला भी कहा जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा बहुत पहले से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए कदम उठा रही थी। पिछले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने अपना राजनीतिक प्रभाव जमाया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। यही आंकड़े तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए दिखाई देने लगे हैं। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनके सामने अपनी राजनीतिक साख बचाने की मज़बूरी है। राजनीतिक आकलन किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ममता केवल और केवल पश्चिम बंगाल तक ही अपना राजनीतिक प्रभाव रखती हैं, अगर किसी कारण से पश्चिम बंगाल भी उनके हाथ से निकल जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस को अपना जनाधार स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि ममता बनर्जी की कार्यशैली को देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि वह आसानी से पराजय स्वीकार कर लेंगी। सभी जानते हैं कि वह स्वयं मोर्चा संभाल लेती हैं। जहाँ तक पश्चिम बंगाल में भविष्य की सरकार बनाने की बात है तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। यह बात भी सही है कि यह दोनों ही राजनीतिक दल मुख्य मुकाबले में हैं। भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने प्रभावी रूप से जनता के बीच उपस्थिति दर्ज करवाकर माहौल को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया, वहीं भाजपा के प्रादेशिक नेताओं ने भी जी तोड़ प्रयास किया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से हर जगह ममता बनर्जी की जनसभाओं की ही मांग हो रही थी, जिसे ममता ने पूरा करने का भी प्रयास किया। मतदान प्रतिशत बढ़ने से भाजपा आशान्वित है, वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब दिखाई दे रही है। अभी पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान ही संपन्न हुआ है। बम्पर मतदान के बाद आम जनता में उत्साह की एक नई लहर का प्रादुर्भाव भी हुआ है। जिसके बाद यह भी संभव है कि दूसरे चरण में भी इसकी पुनरावृति होगी। अगर ऐसा होता है तो यह कहना भी तर्कसंगत ही होगा कि इस बार का मतदान बिना भय के संपन्न हो रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का इतिहास रक्तरंजित है। वामपंथी दलों के शासन से लेकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय हुए सभी चुनावों में हिंसा होती आई है, लेकिन इस बार के चुनावों में इस प्रकार दृश्य का दिखाई नहीं देना, चुनाव प्रबंधन की कुशलता ही मानी जाएगी। पश्चिम बंगाल में यह साफ दिखाई देने लगा है कि इस बार आम जनता भय मुक्त होकर मतदान करने निकल रही है। मतदान प्रतिशत का बढ़ना भी इसी भयमुक्त वातावरण का ही परिचायक है। प्राय: माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी एक सशक्त महिला नेता हैं। आज वे निश्चित रूप से भारतीय राजनीति का एक स्थापित चेहरा हैं। महिला होने के नाते उन्हें महिलाओं की सहानुभूति भी मिलती रही है। लेकिन इस चुनाव में केंद्र भी भाजपा सरकार ने नारी शक्ति को केंद्र मानकर जो वंदन अभियान चलाया, वह भाजपा के लिए एक संजीवनी बनती दिखाई दे रही है।

नेता बनाम जज की पहली बार ऐसी लड़ाई

अभिनय आकाश

क्या किसी केस में आरोपी यह कह सकता है कि जज बदलो वरना पेशी के लिए नहीं आऊंगा। जज से यह कह दे कि आप केस से हट जाइए वरना ना मैं पेश होऊंगा ना मेरी तरफ से कोई वकील आएगा। अब तक शायद आपने ऐसा कोई केस देखा सुना नहीं हो। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर आबकारी नीति केस से नहीं हटी तो ना ही वह पेश होंगे और ना ही उनके वकील। सवाल है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इस बात की इजाजत देती है कि कोई वादी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ मोर्चा खोल दे। इस तरह पेश होने से ही मना कर दे। और क्या केजरीवाल के पहले किसी और ने ऐसा किया है या केजरीवाल ही कोई नज़र पेश करने जा रहे हैं। पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं।

दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी : एक्साइज का मतलब है शराब बेचने का सरकारी नियम। साल 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। बाद में इस पॉलिसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो। साथ ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का अलग केस दर्ज किया। इसी मामले में मनीष सिसोदिया लगभग 500 दिन जेल में रहे। केजरीवाल खुद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार हुए और 156 दिन जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। फिर आया 27 फरवरी 2026 का दिन। दिल्ली के राउस एवन्यू ट्रायल कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता समेत कुल 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब इन पर मुकदमा चलाने लायक सबूत है ही नहीं। इसलिए केस यहीं खत्म। ट्रायल कोर्ट ने अपने आर्डर में सीबीआई की जांच पर सख्त टिप्पणी की और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की सिफारिश तक कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सीबीआई ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह केस जिस जज की बेंच में आया वही हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। 9 मार्च 2026 को इस मामले की पहली सुनवाई हुई। केजरीवाल और बाकी आरोपियों का कहना है कि इस सुनवाई में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी। उनके वकीलों को बुलाया ही नहीं गया और उसी सुनवाई में जस्टिस शर्मा ने प्रथम दृष्ट्या यह पाया कि ट्रायल कोर्ट का आर्डर गलत है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी। ईडी की कारवाई भी टालने को कहा। केजरीवाल का तर्क यह है कि जिस ऑर्डर को बनाने में ट्रायल कोर्ट ने हजारों पन्नों के दस्तावेज पढ़े उसे केवल 5 मिनट की एक तरफा सुनवाई में गलत कैसे कहा जा सकता है? इसके बाद केजरीवाल और पांच और आरोपियों मनीष सिसोदिया, विजय नायर, राजेश जोशी, अरुण रामचंद्रन, पिल्लई और दुर्गेश पाठक ने एक अर्जी दाखिल की। मांग थी कि जस्टिस शर्मा खुद को इस केस से अलग कर लें। इसे कानूनी भाषा में रिकुज़ल कहते हैं। केजरीवाल पक्ष ने तीन मुख्य तर्क रखे। पहला जज के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और इसी केस में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं। दूसरा जस्टिस शर्मा 2022 से 2025 के बीच चार बार अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ माना जाता है। तीसरा 9 मार्च के ऑर्डर की भाषा में लगता है कि अदालत ने पहले ही मन बना लिया है। 20 अप्रैल 2026 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का फैसला आया। 115 पेज का यह ऑर्डर रिकुज़ल की मांग को खारिज करता है।

केजरीवाल ने अपने लेटर में क्या लिखा: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश होने से ही मना कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिख के कह दिया कि अगर केस की सुनवाई आप करेंगी यानी वह करेंगी तो ना तो केजरीवाल खुद आएंगे ना ही उनकी ओर से कोई वकील आएगा। यह वही एक्साइज पॉलिसी वाला केस है जिसमें 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की। मामला जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच में पहुंचा। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता मामले की सुनवाई करेंगी तो वह कोर्ट नहीं जाएंगे, पेश भी नहीं होंगे। चार पेज के लेटर में केजरीवाल ने 25 पॉइंट्स लिखे हैं। कहा कि वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। लेटर के दो खास पॉइंट्स आपको बताते हैं जो केजरीवाल के जस्टिस स्वर्णकांता पर आरोप हैं। चिट्ठी का पॉइंट नंबर छह केजरीवाल कहते हैं कि जब मैंने पहले भी केस में जज बदलने की मांग की थी तब भी यह चिंताएं बताई थी। पहला जस्टिस स्वर्णकांता आरएसएस के लीगल संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से सार्वजनिक रूप से जुड़ी रही हैं। आरएसएस मौजूदा सरकार की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। राजनीतिक रूप से हम केंद्र की सरकार के विरोधी हैं और विचारधारा के स्तर पर मैं और मेरी पार्टी आरएसएस की सोच से सहमत नहीं है। ऐसे में जब जज साहिबा उनके कार्यक्रमों में बार-बार जाती रही हैं तो मुझे कैसे भरोसा हो कि इस अदालत से मुझे न्याय मिलेगा। पॉइंट नंबर सेवन में केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चों का मुद्दा उठाते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि मैं जस्टिस शर्मा का सम्मान करता हूं लेकिन न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसी दुविधा के मौके पर बापू ने हमे सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर भविष्य में भी कभी जज स्वर्णकाता के सामने मेरा कोई दूसरा केस आता है जिसमे मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता नहीं है तो मै उनके समक्ष जरूर पेश होऊगा। आप नेताओ ने केजरीवाल के इस कदम को साहसी कदम बताया। सासद संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के कार्यक्रम में जज स्वर्णकाता शर्मा का कहना कि जब यहां आती हूं, मेरा प्रमोशन हो जाता है, तो उनसे न्याय की उम्मीद क्या की जाए? आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह बेहद साहसी फैसला है, जो व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली शराब नीति मामले में अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने के अभूतपूर्व फैसले के बाद, देश की न्यायिक प्रणाली की पवित्रता विवादों के घेरे में आ गई है। हाल के एक फैसले को चुनौती देने के लिए सामान्य कानूनी रास्तों का पालन करने के बजाय, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक निजी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी वकील के माध्यम से पेश होने से इनकार कर दिया है।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोला था। आपको याद होगा उनकी सिर्फ सरकार ही नहीं गई। केजरीवाल ने उन्हें नई दिल्ली सीट से हराया भी। नितिन गडकरी पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए थे। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष थे सतीश उपाध्याय। उनके खिलाफ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसे एक तरह से केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाने लगा था जिसमें अंधाधुंध आरोपों की फायरिंग होती थी कि बड़े लोगों से लोहा लो। लेकिन बीते कुछ समय से केजरीवाल इस स्टाइल से थोड़ा परहेज करते नजर आ रहे थे या इसका टैक्टिकल उपयोग करते नजर आ रहे थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता पर सीधे सवाल उठाकर केजरीवाल ने अपने पुराने दिन याद दिला दिए हैं जब वो दिल्ली चुनावों से पहले प्रचार करते हुए कुछ पर्चे दिखाया करते थे।

इसका राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही गहरा है। एकानूनी दिग्गज केजरीवाल की इस रणनीति को एक खतरनाक मिसाल बता रहे हैं। केजरीवाल पर अपनी पसंद का जज चुनने का प्रयास करने का आरोप लगाया। भले ही कोई वादी मुकदमा जीतता हो या हारता हो, किसी भी निराशाजनक आदेश के लिए एकमात्र वैध उपाय उच्च अदालत में औपचारिक चुनौती देना ही है। अदालत शक्तिहीन नहीं है, वह जमानती वारंट के माध्यम से मौजूदगी अनिवार्य कर सकती है, या बहिष्कार के बावजूद मामले की सुनवाई जारी रखने के लिए %एमिकस क्यूरी% नियुक्त कर सकती है। यह विवाद केजरीवाल द्वारा मौजूदा बेंच पर व्यक्त किए गए अविश्वास से उपजा है। हालांकि, बार काउंसिल के नियम आम तौर पर यह अनिवार्य करते हैं कि वकील उन अदालतों में पेश न हों जहां जज के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हों।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्याय: (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

पहले यह समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी में सात प्रकार के तैजस पदार्थ पाये जाते हैं, जैसे- सोना, रूपा, ताँबा, राँगा, सीसा, जस्ता और लोहा। लौकिक परिभाषा में इन्हें धातु कहते हैं। यदण्डे तदेव पिण्डे के अनुसार मानव शरीरों में भी रक्त, मेद:, मज्जा, माँस त्वक, अस्थि और शुक्र यह सात घातुवें पाई जाती हैं इस तरह पृथिव्याश्रित तैजस पदार्थों की संख्या सात है, सृष्टि के ग्रारम्भ में उक्त सातों पदार्थ पार्थक्यसीमा तक न पहुंच कर अविशेष तेजओमात्र कलल के रूप में लक्षित होते थे यही दिति रूप पृथ्वी के गर्भ में एकत्वसंख्यावच्छिन्न बालक के होने का तात्पर्य्य है।

पश्चात् अन्तरिक्षस्थ वायु के तारतम्य से वह तैजस तत्तद् धातुओं के रूप में परिणत हो गया। चूंकि मूल धातुवें सात हैं, यही अभिप्राय एक गर्भ के सात टुकड़े कर डालने का है।

वर्तमान वैज्ञानिक भी भली भाँति जानते हैं कि सूर्य की सप्तविध रश्मियें हैं। अतएव धूप में कांच की गोली के संयोग से किम्वा जल

प्रपातों की उच्छाल से साथ तरह के विभिन्न रंग दीख पड़ा करते हैं। वेदादि शास्त्रों में भी सूयं को सप्तरश्मि नाम से याद किया है। सो सूर्य्य की वे सप्तविध रश्मियें भी पार्थिव ऊष्मा के आदान प्रत्यादान में अन्तरिक्षस्थ वायु का पूरा-पूरा साथ देती हैं, अर्थात् पूर्वोबत सप्तविव धातुओं में से प्रत्येक के साथ इन सातों सूर्य्यरश्मियों का संघर्ष होता है।

इस तरह वह पार्थिव ऊष्मा संश्लिष्ट वायु प्रत्येक धातु और तत्संबद्ध प्रत्येक रश्सि के भेद से (7 × 7 = 49) उनंचास भेद वाला ठहरता है। यही गर्भ के सात खण्डों में प्रत्येक के सात सात टुकड़े बना देने का रहस्य है। इसप्रकार यह सपरिकर उनंचास प्रकार के मरुत् अन्तरिक्षस्थ वायु रूप इन्द्र के साथ मिलकर वृष्टि करते हैं।

क्रमश: ...

जब दुर्वासा ने धर्म को दिए तीन शाप

आशुतोष गर्ग

पूर्वकाल में नर्मदा नदी के तट पर अमरकण्टक नाम का प्रसिद्ध तीर्थ था। उसी तीर्थ क्षेत्र में कौशिक वंश में सोमशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए। वह शीलवान और धर्मपरायण थे, परंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण वह सदा दुखी व चिंतित रहते थे। उनकी पत्नी सुमना धर्मनिष्ठ और बुद्धिमती थी। एक दिन सुमना ने अपने पति को चिंतित देखा, तो कहा, 'नाथ, चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, वह शरीर और मन, दोनों को सुखा देती है। आपके दुख का कारण क्या है?' सोमशर्मा बोले, 'मैं न जाने किस पूर्व जन्म के पाप के कारण पुत्रहीन हूं। यही मेरे दुख का मूल कारण है।' सुमना ने कहा, 'नाथ! पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज लोभ है व उसकी जड़ मोह। असत्य उसका तना है और माया उसकी शाखाएं। दंभ तथा कुटिलता उसके पत्ते हैं। कुबुद्धि उसका फूल है एवं अनृत उसकी दुर्गंध। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता और पापाचार में लिप्त प्राणी उस वृक्ष के पक्षी हैं, जो उसकी शाखाओं पर बसे रहते हैं। अज्ञान उसका फल है तथा अधर्म उसका रस। दुर्भाव रूपी जल से वह बढ़ता है और अश्रद्धा उसके फूलने-फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया में संतुष्ट होकर उसके फलों को खाता रहता है, वह चाहे जितना सुखी दिखे, पर पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को न केवल चिंता, बल्कि लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। हमने पूर्व जन्म में न किसी का ऋण लिया है, न किसी की धरोहर छीनी है और न ही किसी से वैर किया है। इसलिए, आप व्यर्थ की चिंता

छोड़ दीजिए।' सोमशर्मा बोले, 'कल्याणी, तुम्हारा वचन सत्य है। फिर भी सच जानने वाले साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। मुझे पुत्र की चिंता है और मैं चाहता हूं कि किसी उपाय से हमें पुत्र प्राप्ति हो।' तब सुमना बोली, 'महाभाग, एक ही गुणवान पुत्र पर्याप्त होता है। बहुत से गुणहीन पुत्र केवल दुख ही देते हैं। फिर उसने कहा, 'एक पुत्र कुल का उद्धार करता है।' आगे उसने कहा, 'पुत्र पुण्य से प्राप्त होता है, उत्तम कुल पुण्य से मिलता है और श्रेष्ठ गर्भ भी पुण्य से ही मिलता है। इसलिए आप पुण्य का आचरण कीजिए। पुण्य करने वाला मनुष्य ही सच्चे सुख का भोग करता है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंचयज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव-ये दस पुण्य के अंग माने जाते हैं। मनुष्य को मन, वाणी और शरीर, तीनों से धर्म का पालन करना चाहिए।' सोमशर्मा ने जिज्ञासावश पूछा, 'प्रिये, धर्म का स्वरूप क्या है और उसके अंग कौन-कौन से हैं? मेरे मन में इसे सुनने की बड़ी इच्छा है।' सुमना बोली, 'अत्रिवंश में उत्पन्न भगवान दत्तात्रेय ही धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय ने अत्यंत कठोर तपस्या की। परंतु दुर्वासा ने कहा कि उन्हें अभी तक धर्म की पूर्ण कृपा नहीं मिली। इस कारण उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने धर्म को तीन शाप दिए-राजा के रूप में जन्म लेने का शाप, दासीपुत्र बनने का शाप और चांडाल योनि में जन्म लेने का शाप। धर्मदेव ने ये तीनों शाप सहर्ष स्वीकार कर लिए। वह राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्मे, दासीपुत्र होकर विदुर कहलाए और राजा हरिश्चंद्र के समय चांडाल बने। इस प्रकार धर्म ने अपने शापों का भोग किया।

युद्ध की आशंकाओं के बीच आशा का सेतु

ललित गर्ग

वैश्विक परिदृश्य इन दिनों युद्ध की अनिश्चितताओं, तनावों और भू-राजनीतिक खींचतान से भरा हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने विश्व अर्थव्यवस्था के सामने कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) केवल एक द्विपक्षीय आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि वैश्विक निराशा के बीच आशा का एक सशक्त संदेश बनकर उभरा है। यह समझौता उस विश्वास को पुनर्जीवित करता है कि सहयोग, संवाद और साझेदारी ही भविष्य की स्थायी समृद्धि का मार्ग हैं। यह समझौता कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। सबसे पहले, इसे मात्र नौ महीनों में अंतिम रूप दिया जाना अपने आप में एक उपलब्धि है, जो दोनों देशों की प्रतिबद्धता और व्यावहारिक कूटनीति को दर्शाता है। दूसरी ओर, यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यापार व्यवस्था में बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठ रहे हैं और देश तेजी से द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन की धीमी गति और जटिलताओं के बीच यह समझौता एक नई दिशा का संकेत देता है, जहां लचीले और उद्देश्यपरक समझौते अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं।

इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय निर्यातकों को लगभग सभी उत्पादों पर शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करना। यह भारतीय उद्योग, विशेषकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग वस्तुएं और प्लास्टिक उत्पाद जैसे क्षेत्रों को इससे अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि भारत में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है, इस समझौते के माध्यम से और अधिक सशक्त होगी। निवेश के क्षेत्र में भी यह समझौता नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। यह निवेश बुनियादी ढांचे, कृषि, तकनीक और सेवा क्षेत्रों मंव नई ऊर्जा का संचार करेगा। जब कोई विकसित देश किसी उभरती अर्थव्यवस्था में इस स्तर का निवेश करता है, तो यह अन्य वैश्विक निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत होता है। इस प्रकार यह समझौता एक 'ट्रिगर पॉइंट' के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भारत में विदेशी निवेश की नई लहर उत्पन्न हो। सेवा क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समझौता और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन और आयुष जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों को लाभ होगा। भारतीय पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड में काम करने के अवसरों का विस्तार, विशेष रूप से हर वर्ष हजारों कार्य वीजा की सुविधा, वैश्विक प्रतिभा प्रवाह को नई दिशा देगा। यह न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा।

इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृषि सहयोग। न्यूजीलैंड अपनी उन्नत कृषि तकनीकों और उच्च उत्पादकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत के पास विशाल भूमि और विविध जलवायु है। दोनों देशों के बीच सहयोग से कीवी, सेब, शहद और अन्य उत्पादों के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। इससे भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, जो इस समझौते की संतुलित प्रकृति को दर्शाता है। वैश्विक दृष्टि से देखें तो यह समझौता उस समय आया है जब दुनिया व्यापार के नए मॉडल तलाश रही है। एक समय था जब वैश्विक व्यापार मुख्यत: केंद्रीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता था, लेकिन अब देश अपने-अपने हितों के अनुसार लचीले और त्वरित समझौते कर रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं, जो उसकी सक्रिय आर्थिक कूटनीति का प्रमाण हैं। यह समझौता भी उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में और गहराई से जोड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समझौते को किसानों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और उद्यमियों के लिए लाभकारी बताना केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि इसकी व्यापक सामाजिक-आर्थिक संभावनाओं का संकेत है। यह समझौता समावेशी विकास की अवधारणा को भी सुदृढ़ करता है, जहां आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि भारत अब किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने की नीति से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में हो रही देरी के बीच भारत का यह कदम उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता और बहुविकल्पीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने लिए नए बाजारों और साझेदारों की तलाश में सक्रिय है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिरता और मजबूती बनी रहे। हालांकि, इस समझौते के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होना होगा। गुणवत्ता, नवाचार और लागत-प्रभावशीलता के क्षेत्र में सुधार आवश्यक होगा। साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस समझौते के लाभ व्यापक रूप से वितरित हों और छोटे तथा मध्यम उद्यम भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके बावजूद, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल है। यह न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह समझौता उस दिशा में एक कदम है, जहां प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे भारत के लिए न्यूजीलैंड के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता केवल एक आर्थिक करार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक छलांग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह समझौता भारत की व्यापारिक सक्रियता, निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजार में उसकी विश्वसनीयता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। इससे भारतीय उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई, कृषि और सेवा क्षेत्रों को नया विस्तार मिलेगा और भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक सशक्त उपस्थिति दर्ज कर सकेगा। इस प्रकार के समझौते यह संकेत देते हैं कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की ओर बढ़ता हुआ एक निर्णायक शक्ति केंद्र बन रहा है। वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य को सामने रखते हुए, ऐसे मुक्त व्यापार समझौते भारत के उज्ज्वल भविष्य के संकेतक प्रतीत होते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार बहुआयामी विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह उसे एक सशक्त, प्रभावशाली और नेतृत्वकारी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये समझौते केवल आर्थिक समृद्धि के साधन नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार करने वाले उपकरण भी हैं। स्पष्ट है कि आने वाला समय भारत के लिए अवसरों से भरा हुआ है, जहां यह देश न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से भी विश्व में अपनी अग्रणी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

आज का इतिहास

1772 जॉन क्लेयस ने प्रथम पैमाने का पेटेंट प्राप्त किया।
1789 जॉर्ज वाशिंगटन ने न्यूयॉर्क शहर के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली।
1789 न्यूयॉर्क में फेडरल हॉल में जॉर्ज वॉशिंगटन का उद्घाटन किया गया, उन्होंने संयुक्त राज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया।
1794 बॉलुओ की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने जनरल यूनियन के तहत स्पेनिश को हराया था।
1803 लुइसियाना खरीद फ्रांस से संयुक्त राज्य द्वारा बनाई गई।
1812 लुइसियाना को 18वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया।
1838 निकारागुआ ने सेंट्रल अमेरिकन फेडरेशन से आजादी की घोषणा की।
1864 न्यूयॉर्क एक शिकार करने के लिए लाइसेंस शुल्क चार्ज करने के लिए सबसे पहला राज्य बना।
1894 1893 के आतंक के कारण बेरोजगारों की भीड़ ने वाशिंगटन, डी.सी. पर पहला महत्वपूर्ण लोकप्रिय विरोध मार्च आयोजित किया।
1943 द्वितीय विश्व युद्ध: रॉयल नेवी पनडुब्बी एचएमएस सेराफ ने सिसिली के आगामी आक्रमण के बारे में जर्मनी को धोखा देने के लिए ऑपरेशन मिंसमीट शुरू किया।
1945 जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने आत्महत्या की।
1948 इक्कीस देशों ने अमेरिकी राज्यों के संगठन की स्थापना करते हुए कोलंबिया के बोगोटा में एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए।
1956 अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति और सीनेटर एल्बेन बार्कली की वर्जीनिया में एक भाषण के दौरान मौत।
1963 ब्रिस्टल में एक बहिष्कार का आयोजन किया गया था ताकि ब्रिस्टल ओम्निबसकम्पेन द्वारा ब्लैक या एशियन बस क्रू को नौकरी देने से इंकार कर दिया जाए, यूनाइटेड किंगडम में नस्लीय भेदभाव के लिए राष्ट्रीयता का चित्रण किया जाए।
1975 वियतनाम युद्ध का अंत हुआ।
1993 महिला टेनिस खिलाड़ी के रूप में नंबर एक स्थान पर रहीं मोनिका सेलेस को एक मैच के दौरान पीछे खड़े खिलाड़ी स्टीफी ग्राफ ने देख लिया था।
1995 लॉरा डेविस ने एलपीजीए चिक-फिल्म-ए चैरिटी गोल्फ चैंपियनशिप जीती।
1997 लंदन एश्योरेंस, 72 प्रदर्शनों के लिए मानदंड थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है।

क्या राहुल गांधी विपक्ष के विश्वसनीय नेता बन पाए हैं?

कल्याणी शंकर

क्या राहुल गांधी जून 2024 में अपनी नियुक्ति के बाद से लोकसभा में एक विश्वसनीय नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं? लगभग दो साल बीत चुके हैं, वह कितने प्रभावी रहे हैं? क्या उन्होंने सरकार को जवाबदेह ठहराया है और बजट समीक्षा के प्रति अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को बदला है? क्या उन्होंने इस दौरान रणनीतिक संचार और गठबंधन बनाने जैसे नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया है? ये प्रश्न उनके प्रभाव और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं। राहुल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में की थी और उन्हें सफलताओं, चुनौतियों और असफलताओं तीनों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार में कोई भी मंत्री पद न लेने का चुनाव करते हुए, जीत और हार के दौरान पर्दे के पीछे से पार्टी का मार्गदर्शन किया।

कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी का एक प्रमुख पद पर आना काफी हद तक अपेक्षित था, जो पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को दर्शाता है। पार्टी की नियुक्तियों में उनका निर्णय अंतिम होता है। कई पार्टी सदस्यों ने उनके नेतृत्व को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा तो अन्य ने इस पर चिंता व्यक्त की कि यह पार्टी में विकल्पों की कमी और नेहरू-गांधी परिवार पर उसकी निर्भरता को उजागर करता है। अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे पार्टी अध्यक्ष बने।

नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल की भूमिका संसद के अंदर और बाहर सरकार की गलतियों को इंगित करना रही है। हालांकि, ऐसे महत्वपूर्ण समय भी रहे हैं जब वह अनुपस्थित थे। राहुल ने संविधान की रक्षा करने, आय असमानता को दूर करने और अन्य मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक मुखर, दृश्यमान भूमिका अपनाई है। उन्होंने औपचारिक भूमिका के अनुरूप अपनी छवि को फिर से गढ़ा है, जिसमें नौकरी सृजन, हाशिए पर पड़े समूहों की सुरक्षा और किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यह एक दशक में पहली बार है कि किसी को कैबिनेट स्तर का पद मिला है। 2014 से, किसी भी विपक्षी दल ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 543 सीटों का 10 प्रतिशत हासिल नहीं किया था।

यह विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में अपने पहले दिन, राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए कानून के शासन को बनाए रखने और विपक्ष के लिए आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, जाति जनगणना और किसानों के संकट जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वह मुख्य चुनाव आयुक्त और सी.बी.आई. प्रमुख जैसे अधिकारियों के चयन में भाग लेते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपक्ष का इन नियुक्तियों में दखल हो।

राहुल की संसद में उपस्थिति अधिक टकराव वाली और मुखर हो गई है, जो सरकार को सीधे चुनौती देने के उनके रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है। सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा मोदी सरकार का जोर-शोर से बचाव करने के कारण संसद में शोरगुल वाले दृश्य सामने आए हैं। विधायी बहसों और पहलों में उनकी सक्रिय भागीदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके बढ़ते प्रभाव और असर को दर्शाती है, जो लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। एक सफल कदम उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसने उन्हें जनता के साथ घुलने-मिलने और उनकी समस्याओं को सीधे जानने की अनुमति देकर उनकी छवि को बढ़ाया। भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षित होने के बाद, उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 2002 में मुंबई लौटने से पहले लंदन में काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त किया।

गांधी को अक्सर उनके आलोचकों द्वारा 'अनिच्छुक राजकुमार' कहा जाता है, जो मानते हैं कि वह अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपनाने में संकोच करते हैं। हालांकि, कई लोग उन्हें लंबे समय से पार्टी में अनौपचारिक 'नंबर दो' मानते हैं। हालांकि, कुछ लोग नेतृत्व के लिए नेहरू-गांधी परिवार पर पार्टी की निरंतर निर्भरता को लेकर चिंतित थे। राहुल ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया और 2004 में अमेठी से एक सीट जीती। सितंबर 2007 में, वह पार्टी के महासचिव बने, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहीं। जनवरी 2013 तक, वह कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर पहुंच गए थे, जो उनके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।

आलोचकों का कहना है कि भले ही वह अब अधिक दृश्यमान हैं लेकिन पार्टी 2024 के अंत और 2025 में प्रमुख राज्य विधानसभा चुनाव हार गई। यह उनकी लोकप्रियता को वोटों में बदलने की क्षमता पर संदेह पैदा करता है। राहुल जून 2024 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जैसे-जैसे समय बीतता है, यदि वह क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन हासिल करने में विफल रहते हैं और स्थानीय राजनीति में संघर्ष करना जारी रखते हैं, तो वह समर्थन खो सकते हैं। विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक बनाया और 2024 के आम चुनाव में एक साथ काम किया। नतीजतन, विपक्ष ने अधिक सीटें जीतीं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर दी। इसकेअतिरिक्त, महत्वपूर्ण आयोजनों में उनकी उपस्थिति और उनके ध्यान केंद्रित करने वाले विषयों के बारे में प्रतिक्रिया मिली है जिन्हें कुछ आलोचक कम महत्वपूर्ण मानते हैं।

वह साधारण लोगों की चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाली गतिविधियों में शामिल होकर अधिक मिलनसार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग समूह उनके प्रदर्शन को अलग-अलग तरह से देखते हैं।

नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के कार्यकाल के दौरान, वह एक अधिक केंद्रित और स्पष्टवादी नेता बन गए हैं। हालांकि, क्या उन्होंने 'विश्वसनीयता' हासिल की है? यह व्यक्तिपरक मुद्दा है। समर्थक सुधार देखते हैं, जबकि विरोधी तर्क देते हैं कि उनकी शैली में कोई बदलाव नहीं आया है।

बंगाल विधानसभा चुनाव: दीदी के चुनाव क्षेत्र में क्यों नहीं गए मोदी?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में नारा दी थी- अबकी बार दो सौ पार। चुनाव परिणाम आने के बाद सौ भी पार नहीं हुआ तो बीजेपी समर्थकों ने ही कहना शुरू किया कि मोदी-दीदी में सेटिंग है। धीरे धीरे पांच साल में जंगल की आग की तरह यह फैल गया।

2026 के विधानसभा चुनाव में मोदी, दीदी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर गए ही नहीं। न सिर्फ भवानीपुर बल्कि दक्षिण कोलकाता में ही नहीं गए। जबकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अन्य दो स्टार प्रचारक शाह और योगी भी नहीं गए।

बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक ही अब यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर यह तीनों इस चुनाव क्षेत्र में क्यों नहीं गए! फिर एक बार मोदी-दीदी की सेटिंग की चर्चा जोर पकड़ रही है। मोदी अपने आखिरी चुनाव प्रचार बैरकपुर में भी दीदी का नाम एकबार भी नहीं लिए!

मार्च के अंतिम सप्ताह में बीजेपी से ही खबर थी कि मोदी दक्षिण कोलकाता में रोड शो करेंगे, यह भवानीपुर और रासबिहारी विधानसभा को कवर करेगा। अप्रैल के मध्य में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से एसपीजी ने अनुमति नहीं दी है। सिलीगुड़ी में भी एसपीजी से रोड शो की अनुमति नहीं मिलने के बाद जनसभा आयोजित की गई थी।

मोदी बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल रोड शो और जनसभा 19 किये। उत्तर कोलकाता में भी रोड शो किये लेकिन दक्षिण कोलकाता में गए ही नहीं। अमित शाह हालांकि नामांकन के दिन शुभेंदु अधिकारी के साथ रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे।

बीजेपी तर्क दे रही है कि ब्रिगेड की रैली में मोदी शामिल हुए थे, ब्रिगेड और भवानीपुर दोनों दक्षिण कोलकाता में आता है। मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 14 मार्च 2026 को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर एक विशाल रैली को संबोधित किया था। यह रैली चुनाव घोषणा होने के पहले हुई थी। चुनाव की घोषणा 15 मार्च 2026 को हुई थी।

टीएमसी ने इस पर कटाक्ष भी किया है। टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के एक दिन पहले तक हिटलर कहता रहा कि जीत जर्मनी की होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी-शाह जानते हैं कि बंग विजय नहीं होगा, इसलिए नहीं आकर किरकिरी होने से अपने को बचा रहे हैं।

दूसरी तरफ, एक रैली में ममता बनजी ने दहाड़ते हुए कहा मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। इस बयान ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यह बात क्यों कही? कहीं यह किसी बहुत बड़े सियासी तूफान के आने से पहले की खामोशी भरी आहट तो नहीं है!

बहरहाल, सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी चुनाव हार रही है? क्या ममता बनर्जी राजनीतिक संन्यास ले रही हैं? क्या ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति करेंगी? क्या अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगीं? तमाम इस तरह के सवाल राजनीतिक माहौल में तैर रहे हैं।

लोकतंत्र में लोक की आस्था का प्रमाण- बम्पर मतदान

मृत्युंजय दीक्षित

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुआ अभूतपूर्व बम्पर मतदान लोकतंत्र में लोक की आस्था का प्रमाण है। यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। यह बताता है कि भारत के आम नागरिक का अपने संविधान, संवैधानिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं पर कितना अटूट विश्वास है। राजनैतिक दलों के लिए इस मतदान में क्या छुपा है वो तो 4 मई 2026 को ज्ञात होगा किन्तु जनता जनार्दन अपना कर्तव्य निभाने में जीत चुकी है।

राजनैतिक विश्लेषक बंगाल में बंपर मतदान के पीछे कई कारण बता रहे हैं जैसे कि मतदाता जागरूकता अभियानों में लगातार वृद्धि, महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी, बेहतर चुनाव प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्थानीय मुद्दों पर जागरुकता। बंगाल में एक बड़ा कारण जनमानस में राजनीतिक चेतना जाग्रत होना भी माना जा रहा है। कुछ लोग एसआईआर के कारन कम हुए मतदाताओं को ही इसका एकमात्र कारण बता रहे हैं जबकि कुछ लोग टीएमसी व बीजेपी द्वारा अपने-अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रो तक पहुंचाने को भी महत्वपूर्ण कारण मान रहे हैं। चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं अत: भयमुक्त वातावरण स्वाभाविक रूप से यहाँ अधिक मतदान का एक कारण है। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 2 लाख 40 हजार जवानों की तैनाती की गई है और अधिकतर सीटों पर मतदान शांत रहा है। पश्चिम बंगाल में रिकार्ड मतदान ने चुनावी मनोविज्ञान पूरी तरह से बदल दिया है और चुनावी सर्वे करने वाली संस्थाओं को भी हैरान कर दिया है।

सभी के मन में यह प्रश्न है कि क्या भयमुक्त वातावरण में हुआ भारी मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है ? इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बंगाल में भाजपा बहुत मजबूती से करो या मरो के जूनून से चुनाव लड़ रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के चालीस स्टार प्रचारकों ने पूरे बिहार को मथ डाला है। ठेठ बंगाली में बोलती स्मृति ईरानी, भीड़ खींचती कंगना रानौत, लोगों का मन मोहती मैथिली के साथ साथ हिंदुत्व को धर देते योगी जी और हिमंता जी और फिर स्वयं गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी।

भाजपा इतने उत्साह में है कि उसकी ओर से पहले चरण के बाद ही घोषणा तो कर दी गई है कि महाजंगलराज का समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतामुक्त होकर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे समय बिता रहे हैं हुए और नौका विहार का आनंद लेते हुए फोटोग्राफी कर पूरी दुनिया को कोलकोता दर्शन करा रहे हैं। ये बात और है कि इससे बंगाल का चुनावी वातावरण गर्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मां गंगा का बंगालियों के जीवन में एक विशेष स्थान है, इसका जल एक प्राचीन सभ्यता की भावना को अपने साथ समेटे हुए है। उन्होंने लिखा कि कोलकाता में मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया यह मा गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। हुगली के तट पर मैंने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की समृद्धि के लिए काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने यह भी बताया कि नौका विहार के दौरान उन्हें प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को देखने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होने नाव की सवारी कराने वाले नाविक को गले लगाया। जब प्रधानमंत्री मोदी नाव की सवारी कर रहे थे उस समय नदी के तट पर हजारों की भीड़ एकत्र हो गई और मोदी-मोदी के नारे लगाने लगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह नौका विहार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अब भय जा रहा हे और भरोसा आ रहा है। पीएम मोदी ने एक अत्यंत विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। पहले चरण के मतदान से बीजेपी की विजय का शखनाद हो चुंका है। पीएम मोदी ने अगले चरण के लिए कहा कि अब आपको अगले चरण में विजय पताका फहरानी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दीया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए टीएमसी से आजादी बहुत जरूरी है।

माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिन 152 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है वहां भाजपा की स्थिति अच्छी थी किंतु अगला चरण भाजपा की अग्निपरीक्षा से कम नहीं है क्योकि इन 140 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी का व्यापक प्रभाव है। पिछली बार यहाँ पर टीएमसी ने 89 सीटें जीती थीं। अगर यह बात सही है कि बंगाल के प्रथम चरण के मतदान में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर टीएमसी को और हिंदू बाहुल्य सीटों में 65 प्रतिशत से अधिक हिंदू मतदाताओं ने भाजपा को मत दिया है और यही रुख अगले चरण में भी रहता है तो यह अधिक मतदान बंगाल में परिवर्तन के लिए ही है।

प्रथम चरण के मतदान के बाद ममता दीदी के पक्ष में केवल शिवसेना के संजय राउत ने बयान जारी कर कहा है कि बंपर मतदान एसआईआर के खिलाफ आक्रोश है जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता दबी जुबान से कुछ और ही बयान दे रहे हैं।

यद्यपि चुनाव पांच प्रान्तों में हो रहे हैं किन्तु पूरे भारतीय जनमासनस की दृष्टि बंगाल में अटकी है। भीषण गर्मी के बीच लगभग 93 प्रतिशत मतदान हो जाने के बाद भारतीय जनता पाटी और अधिक आक्रामकता के साथ प्रचार कर रही है। बंगाल के विधानसभा चुनावों में इस बार मुर्शिदाबाद और कुछ अन्य जगहों को छोड़कर कहीं और व्यापक हिंसा नहीं हुई। बंगाल के मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर जो बंपर उत्साह दिखाया है उसे ममता दीदी एसआईआर के खिलाफ जनता का आक्रोश बता रही हैं और पहली बार उन्होंने यह कह दिया है कि बीजेपी को कैसे पता कि वह बंगाल में जीत रही है क्या उन्होंने ईवीएम को फिक्स कर लिया है। यह बात तय हो गई है कि अगर 4 मई को बंगाल से ममता की सरकार जाती है तो वह चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली, एसआईआर और ईवीएम पर ही निशाना साधेंगी।

दलबदल कानून के घेरे में 7 'आप' राज्यसभा सांसदों का भविष्य

कांतिलाल मांडोत

देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी में आई इस बड़ी टूट ने न केवल पार्टी के आंतरिक हालात को उजागर किया है बल्कि दलबदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता और उसकी सीमाओं पर भी नई बहस छेड़ दी है। राज्यसभा के कई सांसदों द्वारा पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा के बाद अब यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या ये सांसद अपनी सदस्यता बनाए रख पाएंगे या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।

इस पूरे मामले के केंद्र में हैं राघव चड्ढा जिनके साथ कई अन्य सांसदों ने भी पार्टी छोड़ने का दावा किया है। इनके साथ संदीप पाठक अशोक मित्तल विक्रम साहनी हरभजन सिंह स्वाति मालीवाल और नरेंद्र गुप्ता जैसे नामों का भी उल्लेख किया जा रहा है। इन सभी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा का रुख किया है। इस दावे ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया है।

दूसरी ओर संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन को याचिका सौंपकर इन सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन सांसदों ने संविधान की दसवीं अनुसूची का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो दलबदल को रोकने के लिए बनाई गई थी।

भारत में दलबदल विरोधी कानून जिसे दसवीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों में स्थिरता बनाए रखना और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था। इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

इस कानून में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पार्टी व्हिप से जुड़ा हुआ है। यदि कोई सांसद सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो भी उसे अयोग्यता का सामना करना

पड़ सकता है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी अनुशासन बना रहे और सरकार या विपक्ष की रणनीति प्रभावित न हो।

निर्दलीय सदस्यों के लिए भी इस कानून में स्पष्ट नियम हैं। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता जिस स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनते हैं वह बाद में किसी दल का हिस्सा बनकर उनकी अपेक्षाओं के साथ समझौता न करे।

हालांकि इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है जिसे विलय का प्रावधान कहा जाता है। इसके अनुसार यदि किसी दल के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्य एक साथ किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दलबदल नहीं बल्कि वैध विलय माना जाता है और ऐसे सदस्यों को अयोग्यता से छूट मिल जाती है। यही वह बिंदु है जिस पर इस पूरे मामले का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा।

अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के इन सांसदों की संख्या दो तिहाई के आंकड़े तक पहुंचती है या नहीं। यदि यह संख्या पूरी होती है तो ये सांसद अपनी सदस्यता बचा सकते हैं अन्यथा इन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और राजनीतिक गणित तेजी से बदल रहा है।

इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास होता है। वर्तमान में यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पास है जो इस मामले की सुनवाई करेंगे और तथ्यों के आधार पर फैसला देंगे। उनका निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वही तय करेगा कि संबंधित सांसद संसद में बने रहेंगे या नहीं।

हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सभापति का निर्णय अंतिम होने के बावजूद न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि दलबदल से जुड़े मामलों में सभापति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब है कि यदि किसी पक्ष को निर्णय से असंतोष होता है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। यदि बड़ी संख्या में सांसद दलबदल कर बिना अयोग्यता के बच जाते हैं तो यह अन्य दलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। वहीं यदि कड़ी कार्रवाई होती है तो यह संदेश जाएगा कि दलबदल कानून अभी भी प्रभावी है और उसका उल्लंघन करने पर सख्त परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दलबदल विरोधी कानून अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा कर पा रहा है या इसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून का उपयोग कई बार राजनीतिक हथियार के रूप में भी किया जाता है जिससे विधायकों और सांसदों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि यह कानून न हो तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है और सरकारें गिरने का खतरा बना रह सकता है।

आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ जनता और संवैधानिक संस्थाओं के सामने अपनी बात रखेंगे। इस पूरे मामले पर देश की नजर बनी हुई है क्योंकि यह केवल सात सांसदों का मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अंतत: यह कहा जा सकता है कि दलबदल कानून भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इसका उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो ताकि लोकतंत्र की मूल भावना बनी रहे। आने वाले समय में सभापति का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देगा और यह तय करेगा कि राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति पर कितना नियंत्रण संभव है।

लोकतंत्र पर हावी चुनावतंत्र

अरविंद मोहन

यह आलेख लिखे जाने तक बंगाल के अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। चुनाव हर बार ज्यादा दिलचस्पी जगाते हैं, उनके नतीजों का असर सामान्य दिखने की तुलना में ज्यादा गहरा होता है लेकिन बंगाल का इस बार का चुनाव पड़ोस के असम या साथ चुनाव में उतरे तमिलनाडु और केरल से कहीं ज्यादा दूरगामी असर वाला है, इसकी विकृतियां ज्यादा बड़ी हैं। यह सब कहने का मतलब यही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद वहां जो कोई सत्ता में आए या केंद्र में बैठे बड़े लोग हों, सबको बहुत ठंडे मन से चुनाव के पूरे क्रम और अपने कामों पर भी गंभीरता से सोचना होगा और चीजें सुधारने की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन यह भी लगता है कि अगर एक दशक तक गंभीरता से काम हो, तब शायद सुधार हो पाएगा। इसमें लोगों की मुस्तैदी भी जरूरी है। लेकिन आज चुनाव ऐसा बन चुका है कि चीजें कहां से संचालित होती हैं, कहना मुश्किल है और लोगों के पास एक बटन दबाने में विवेक दिखाने के अलावा ज्यादा कुछ बचा नहीं है। शायद उससे ही चमत्कार हो जाए। चुनावी खर्च मुद्दा नहीं रह गया है और बंगाल चुनाव में भी ज्यादा बड़ा मुद्दा हो, लगा नहीं। अदने से विधायक हुमायूं कबीर को हजार करोड़ रुपए देने की पेशकश और उनका कबूलनामा भी मुद्दा नहीं बन पाए। बाकी कितना पैसा पकड़ा गया, कितनी शराब जब्त हुई, टाइप सूचनाओं से तो अब खर्च का हिसाब नहीं लगता। सभी दलों के मंडराते दर्जनों हैलीकाप्टर या चार्टर्ड विमानों का चुनावों पर कितना खर्च आया होगा, यह सोचा जा सकता है। हां इस बार बंगाल में बाहर से बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में गए वोटर ढोकर लाए गए, उसकी चर्चा जरूर हुई। पर हिंसा के मामले में तृणमूल कमजोर पड़ी हो, यह कहना मुश्किल है। भाजपा ने अपने भर प्रयास किया। और चाहे केन्द्रीय बलों की ताकत से हो या जैसे भी, लेकिन चुनाव अगर हिंसा से मुक्त हों, या इस बार पहले की तुलना में कम हिंसा हुई हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। टिकट बाहुबलियों को दिए गए। यह क्या है और इसके पीछे की मंशा क्या है, यह समझना आसान नहीं है। पर बंगाल चुनाव में हिंसा की परंपरा बनाने में वाम दलों की भी भूमिका रही है। और अगर कभी बिहार के चुनाव हिंसा के लिए बदनाम थे तो आज वह बदल चुका है। लेकिन बंगाल में चुनाव देश भर में सबसे ज्यादा हिंसक क्यों हैं, इस पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी को भी सोचना होगा। इस बार बंगाल चुनाव मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और आखिरी दिन तक अदालती आदेश से वोट का हक पाने की उम्मीद लगाए लाखों वोटर मायूस हुए। योगेंद्र यादव का कहना है कि अक्तूबर 2025 को, अर्थात इस अभियान के शुरू होने से पहले राज्य की वयस्क आबादी 7.67 करोड़ थी और राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़। साफ है कि यहां ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले 58 लाख नाम काटे और फिर 60 लाख नामों पर 'लाजिकल डिस्क्रिपैंसी' का लाल झंडा गाड़ दिया गया। इनमें से ज्यादातर वोट के अधिकार से वंचित हुए। किस-किस तरह की गलतियां सामने आईं, यह गिनवाना बहुत होगा लेकिन जब लोग कलैक्टर को घेरने तक पहुंच गए, तब भी मामले को एकतरफा रखा गया। अदालती दखल भी चुनाव आयोग की तरफ झुका था। और जब इसी क्रम में ई.डी. के इस्तेमाल और सीधे मुख्यमंत्री द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया तो फिर इस सारे शुद्धिकरण अभियान की गंदगी जिसे न दिखी हो, वही अंधा कहलाएगा। हर राज्य में नामों में कतर-ब्योंत हुई, लेकिन बंगाल की तरह कहीं नहीं हुई। और यही कारण रहा कि ममता शासन के 15 साल का रिकार्ड और उससे पैदा नाराजगी के मुख्य चुनावी मुद्दा बनने की जगह मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही मुख्य मुद्दा बन गया। पता नहीं इससे ममता को लाभ होगा या भाजपा की मंशा इस बार पूरी हो जाएगी, यह 4 मई को साफ होगा। बंगाल जीतने की तमन्ना भाजपा के नेताओं के अंदर इस कदर हावी रही है कि उन्होंने सब कुछ किया और ममता बनर्जी ने भी जवाब देने में कमी नहीं की। इससे पहले चुनाव में मातुआ के नाम पर बंगाल के शांत समाज में जाति की फूट पैदा करने की कोशिश हुई तो उससे पहले हिन्दू-मुसलमान ध्रुवीकरण का प्रयास हुआ।

काजोल और बेटी नीसा के बीच होते थे खूब झगड़े

गुस्से में एक्ट्रेस ने तोड़ा था फोन, मां-बेटी इन 5 तरीकों से संभालें हालात

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और उनकी बेटी नीसा देवगन की तरह अगर आपके और आपकी टीनएज बेटी के बीच झगड़े हो रहे हैं, तो दोनों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मां के तौर पर आपको पहले बेटी को सलाह देने से पहले उन्हें ध्यान से सुनें। वहीं बेटियों को चाहिए कि वे मां के लहजे पर ध्यान देने के बजाय उनकी फ़िक्र को समझें।

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि जब उनकी बेटी नीसा देवगन करीब 12 साल की थीं, तब दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक बार गुस्से में उन्होंने फोन भी तोड़ दिया था। मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर समझाना जरूरी है कि 12 से 17 साल की उम्र में, सबसे करीबी रिश्तों यानी बच्चों और माता-पिता के बीच भी तनाव आ सकता है।

इसकी वजह यह है कि टीनएज में बच्चों की सोच, भावनाएं और व्यवहार तेजी से बदलते हैं। इसका असर मां-बेटी के रिश्ते पर भी पड़ता है, जिससे दोनों को कभी-कभी उलझन, दुख और निराशा महसूस होती है। हालांकि, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मां और बेटी दोनों को धैर्य, समझ और आपसी बातचीत बनाए रखना बहुत जरूरी है।

दिमाग नहीं होता विकसित

सबसे पहले पेरेंट्स को यह समझना जरूरी है कि टीनएजर्स का दिमाग इस वक्त में लगातार विकसित हो रहा होता है। ब्रेन का वह हिस्सा, जो सही-गलत समझने, गुस्सा कंट्रोल करने और दूसरों की बात समझने में मदद करता है, लगभग 25 साल तक पूरी तरह विकसित होता है। इसी वजह से कई बार बच्चा चीजों को अलग तरीके से समझ लेता है। मां की चिंता उसे आलोचना लग सकती है, साधारण सवाल पूछताछ जैसा महसूस हो सकता है, और प्यार से बनाए गए नियम उसे रोक-टोक जैसे लग सकते हैं।

बच्चे बनाना चाहते हैं अपनी पहचान: इस उम्र मेंबच्चे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। एक लड़की भी अपने परिवार, खासकर मां से अलग खुद को समझने और पहचान बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में जब मां उसे समझाती या सुधारती है, तो उसे लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है या उसे कंट्रोल किया जा रहा है।

इमोशन्स संभालने की नहीं होती क्षमता: इस उम्र में लड़कियां भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होती हैं। यह जिद या नाटक नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उनके इमोशन्स को संभालने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसलिए जो बात मां को सामान्य लगती है, वही बात बेटी को बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है।

प्यार की कमी नहीं होती है यह

मां और बेटी दोनों को यह समझना जरूरी है कि यह प्यार की कमी नहीं है। यह एक स्वाभाविक बदलाव है, जहां बच्चा बड़ा हो रहा होता है और अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। असल में, यह स्थिति जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और विकास तीनों के टकराव का नतीजा होती है। इसीलिए इस स्थिति को मां और बेटी दोनों को ही बेहद सावधानी से स्थिति को संभालना चाहिए।

मदर्स इस स्थिति को कैसे संभालें:

पहले सुनें, फिर सलाह दें: टीनएजर्स को कोई भी बात समझाने ये गाइड करने से पहले उन्हें यह महसूस करना जरूरी है कि उनकी बात सुनी जा रही है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले उन्हें ध्यान से सुनें।

जरूरी बातों पर ही सख्ती रखें: हर छोटी बात पर बहस जरूरी नहीं है। सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दें जो सच में महत्वपूर्ण हैं।

भावनाओं को समझें: पहले बेटी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। मगर इस बात का यह मतलब कतई न निकालें कि आप उसकी हर बात से सहमत हैं, बस यह कोशिश इसीलिए है की इससे भरोसा बढ़ता है।

अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से बताएं: बेटियों से अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन अपनी भावनाओं का बोझ बेटी पर न डालें।

माफी मांगना सीखें: अगर आपसे गलती हो जाए, तो उसे मान लें। इससे आप उसे भी जिम्मेदार और समझदार बनना सिखाती हैं।

बेटियों को समझनी चाहिए ये 5 बातें:

लहजे को नजरअंदाज करें: बेटियों को यह समझने की जरूरत है की कभी-कभी मां का बोलने का तरीका सख्त लग सकता है, लेकिन उनकी चिंता आमतौर पर सच्ची होती है।

शांति से स्पेस मांगें: इस वक्त में झगड़ा करने के बजाय आप मां से साफ और शांति से कहें कि आपको थोड़ा खुद के लिए वक्त चाहिए।

खुद से शेयर करें: अपनी छोटी-छोटी बातें खुद बताने से मां की चिंता और सवाल कम हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें की उनसे शेयर करें।

धैर्य रखें: आपकी मां भी इस नए दौर को समझ रही हैं। उनके पास भी हर बात का जवाब नहीं होता, इसलिए उन्हें भी समय दें। झगड़े के बाद सुलह करें: अगर बहस हो जाए, तो बाद में 'सॉरी' कहना या मान लेना कि बात बिगड़ गई थी, बहुत जरूरी है। इससे दोनों के बीच भरोसा कायम होता है।

बातचीत जारी रहना है बेहद जरूरी

किशोरावस्था में मां-बेटी का रिश्ता मुश्किलों से टूटता नहीं है, बल्कि यह उसी तरह आगे बढ़ रहा होता है जैसा उसे होना चाहिए। इस समय होने वाले छोटे-छोटे मनमुटाव इस वक्त का अहम हिस्सा होते हैं। ध्यान रखें की जो परिवार मजबूत बनकर निकलते हैं, वे वो नहीं होते जो झगड़ों से बचते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर हाल में बातचीत जारी रखते हैं।

बच्चों को नाश्ते में चाय-बिस्कुट बिल्कुल न दें

बढ़ सकता है एनीमिया का खतरा, ये 5 जोखिम भी हैं शामिल

कभी बच्चों की जिद तो कभी जल्दबाजी में माता-पिता उन्हें नाश्ते में चाय और बिस्कुट दे देते हैं। लेकिन यही आदत धीरे-धीरे उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। यह स्नैक्स बच्चों को जरूरी पोषण नहीं देता और इससे एनीमिया (खून की कमी) का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए, जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए हेल्दी और पौष्टिक नाश्ते के विकल्प चुनें।

आमतौर पर कई घरों में सुबह की शुरुआत चाय और बिस्कुट या हल्के स्नैक्स से होती है। जब बड़े ऐसा करते हैं, तो बच्चे भी यही आदत अपना लेते हैं। खास बातचीत में डॉक्टर गोपाल ने बताया की यह आदत बच्चों के लिए सही नहीं है। चाय और बिस्कुट से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता। लंबे समय तक ऐसा नाश्ता करने से बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है।

इसलिए जरूरी है कि बच्चों को हेल्दी नाश्ते के विकल्प दिए जाएं, जैसे वेजिटेबल पोहा, पनीर स्टफिंग वाला चीला और अन्य पौष्टिक चीजें। नीचे पेरेंट्स इसके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं।

आखिर चाय-बिस्किट अनहेल्दी क्यों हैं?

सुबह का नाश्ता बच्चे के पूरे दिन की ऊर्जा, दिमाग के काम (कॉग्निटिव फंक्शन) और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। वहीं, चाय-बस्किट में पोषण न के बराबर होता है। बस्किट ज्यादातर मैदा, चीनी और अनहेल्दी फैट से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल जैसे जरूरी पोषक तत्व लगभग नहीं के बराबर होते हैं। वहीं, चाय में भी कोई खास पोषण नहीं होता। ऐसे में चाय और बिस्कुट मिलकर सिर्फ 'खाली कैलोरी' देते हैं, जो पेट तो भरते हैं लेकिन शरीर को जरूरी ताकत और पोषण नहीं देते।

बढ़ता है एनीमिया का खतरा: चाय में टैनिन नाम का तत्व होता है, जो शरीर में आयरन को सही तरीके से अवशोषित होने से रोकता है। अगर बच्चे रोज सुबह चाय पीते हैं, तो उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और आगे चलकर एनीमिया (खून की कमी) का खतरा बढ़ जाता है। इससे बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है।

चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है: बिस्कुट में चीनी ज्यादा होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है। इस उतार-चढ़ाव की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, उनका ध्यान कम लगने की शिकायत हो सकती है और बार-बार कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा होने लगती है।

हेल्दी नाश्ते के आसान विकल्प

मूंगफली के साथ वेजिटेबल पोहा
दही के साथ होल व्हीट वेजिटेबल पराठा
दूध और फलों के साथ ओट्स दलिया
सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली
पनीर स्टफिंग वाला बेसन चिल्ला
होल ग्रेन टोस्ट के साथ उबले अंडे
मेवे और बीजों के साथ फ्रूट स्मूदी
सब्जियों के साथ उपमा
सादा या मीठा दलिया
दूध के साथ पीनट बटर या पनीर सैंडविच

सिजेरियन के बाद जल्द दूसरी प्रेग्नेंसी हो सकती है खतरनाक

डॉक्टर से जानिए कारण और सही समय

सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला के शरीर को पूरी तरह रिकवर होने में समय लगता है। अगर शरीर को पर्याप्त समय न मिले और जल्दी फिर प्रेग्नेंसी हो जाए, तो मां की सेहत पर असर पड़ सकता है और कई जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसी वजह से मैं बतौर डॉक्टर निर्धारित अंतराल के बाद ही अगली गर्भावस्था की योजना बनाने की सलाह देती हूं।

मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां महिलाओं ने सिजेरियन डिलीवरी के बाद पर्याप्त समय नहीं दिया और जल्दी ही दूसरी बार प्रेग्नेंसी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रेटा जैसी जोखिमों का सामना करना पड़ा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सिजेरियन के बाद अगली गर्भावस्था की योजना बनाते समय कम से कम 18 से 24 महीने का अंतर रखना चाहिए। इससे गर्भाशय के अंदरूनी घाव ठीक से भर पाते हैं और महिला का शरीर पूरी तरह रिकवर हो जाता है। कपल्स को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए और सोच-समझकर सही समय पर ही अगली गर्भावस्था की योजना बनानी चाहिए।

गैप आखिर जरूरी क्यों है?

दो प्रसवों के बीच लगभग 2 साल का अंतर रखने की सलाह दुनिया भर की मेडिकल गाइडलाइंस और लंबे समय के क्लीनिकल अनुभव पर आधारित है। यह अंतराल गर्भाशय को पूरी तरह से मजबूत होने का अवसर देता है और अगली गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का जोखिम भी कम करता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि रिकवरी सिर्फ बाहरी घावों तक सीमित नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदरूनी ऊतकों को ठीक होने में भी अधिक समय लगता है। इसके अलावा, इस अवधि में शरीर के पोषक तत्वों का संतुलन भी फिर से बेहतर हो जाता है, जिससे अगली गर्भावस्था मां और बच्चे दोनों के लिए अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बन सकती है।

प्रेग्नेंसी में हो सकती हैं ये कॉम्प्लिकेशन्स

सी-सेक्शन के बाद अगर अगली गर्भावस्था के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो कई कॉम्प्लिकेशन्स का खतरा बढ़ सकता है। इनमें सबसे गंभीर जोखिम गर्भाशय फटने यानी की यूट्राइन रप्चर का होता है, जिसमें पुराने ऑपरेशन का घाव दबाव पड़ने पर कमजोर होकर फट सकता है।

यह एक इमरजेंसी मेडिकल स्थिति होती है, जिसमें मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा से जुड़ी समस्याएं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रेटा का खतरा भी बढ़ सकता है।

पार्टनर शक करता है? बड़े कारण और भरोसा वापस लाने के आसान तरीके!

रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब उसी भरोसे में दरार आने लगे तो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आप पर शक करने लगता है, भले ही आपने कुछ गलत न किया हो। यह शक धीरे-धीरे रिश्ते में तनाव, लड़ाई और दूरी का कारण बन सकता है।

शक करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पिछला बुरा अनुभव, बातचीत की कमी या फिर आत्मविश्वास की कमी। अगर समय रहते इस समस्या को समझकर सुलझाया न जाए, तो यह रिश्ता टूटने तक की नौबत ला सकता है।

सही समझ और कुछ आसान उपायों से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पार्टनर क्यों शक करता है और आप कैसे इस शंका को खत्म करके अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकते हैं।

कई बार आपके पार्टनर के पिछले रिश्तों में धोखा मिला होता है, जिसकी वजह से वह आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। यह उनका डर होता है, न कि आपकी गलती। ऐसे में धैर्य और समझ जरूरी है।

अगर आप अपने दिन, दोस्तों या योजनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं करते, तो पार्टनर के मन में शंका पैदा हो सकती है। छोटी-छोटी बातें भी शेयर करना रिश्ते को मजबूत बनाता है।

कुछ लोग स्वभाव से ज्यादा सोचते हैं और छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। आत्मविश्वास की कमी भी शक की बड़ी वजह बनती है। उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें शक करने पर मजबूर कर देती है। आज के समय में सोशल मीडिया भी शक का कारण बन सकता है। ऑनलाइन एक्टिविटी, चैट्स या लाइक्स को लेकर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं।

भरोसा वापस कैसे लाएं

भरोसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी और निरंतर प्रयास।

अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखें। पार्टनर को समय दें। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं।

प्राइवेट और सरकारी वैक्सीन में क्या फर्क है?

बच्चों को समय-समय पर वैक्सीन लगवाई जाती है ताकि वे बीमारियों और इंफेक्शन से सुरक्षित रह सकें। लेकिन पेरेंट्स अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सरकारी या प्राइवेट वैक्सीन में से क्या बेहतर है। एक एक्सपर्ट के तौर में यह कहता हूं कि दोनों ही विकल्प सुरक्षित और प्रभावी हैं, और इनके असर में कोई अंतर नहीं होता।

अक्सर मुझसे कई पेरेंट्स यह सवाल करते हैं कि प्राइवेट और सरकारी वैक्सीन में क्या अंतर होता है और क्या सरकारी वैक्सीन कम असर करती है। बतौर डॉक्टर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दोनों ही वैक्सीन एक जैसे मानकों पर बनी होती हैं और समान रूप से असरदार होती हैं। इसलिए पेरेंट्स को किसी भी भ्रम में न पड़कर समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए।

वैक्सीन एक मेडिकल प्रोडक्ट है, जो लोगों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। यह शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ताकि वह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सके। टीके में कीटाणुओं का कमजोर, मरा हुआ रूप, या उनसे मिलते-जुलते पदार्थ होते हैं। इससे शरीर बिना बीमार हुए ही एंटीबॉडी बनाना सीख जाता है और आगे चलकर बीमारी से बचाव करता है।

बच्चों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण (वैक्सीनेशन) है। इससे खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाव होता है। ये बीमारियां कई बार जिंदगी भर की परेशानी, गंभीर दिक्कतें या यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकती हैं। वहीं, छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह मजबूत नहीं होता, इसलिए वे संक्रमणों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में टीके उन्हें इन बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

सरकारी और प्राइवेट टीकों में मुख्य फर्क उनकी उपलब्धता, कीमत और कवरेज का होता है। सरकारी टीके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाना होता है, ताकि मौत और गंभीर बीमारियों के मामलों को कम किया जा सके। वहीं, प्राइवेट टीके निजी अस्पताल या क्लीनिक में मिलते हैं और इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि, इनमें कुछ ऐसे टीके भी शामिल होते हैं जो सरकारी सूची में नहीं होते। कुछ प्राइवेट टीके ज्यादा बीमारियों से सुरक्षा देते हैं या खास और कम होने वाली बीमारियों से भी बचाव करते हैं।

भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कई जरूरी टीके फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं, जो बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। इनमें बीसीजी, पोलियो (ओपीवी/आईपीवी), हेपेटाइटिस बी, पेंटावैलेंट वैक्सीन (डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेसऔर हेपेटाइटिस बी), रोटावायरस, खसरा-रूबेला (एमआर) और डीपीटी बूस्टर शामिल हैं।

माता-पिता भी होते हैं स्वार्थी, अपने फायदे के लिए चुनते हैं फेवरेट बच्चे

कई परिवारों में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जहां पेरेंट्स बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करते या किसी एक बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं। यह स्थिति दूसरे बच्चे के लिए भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल हो सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना चाहिए और फिर शांत तरीके से अपने माता-पिता से खुलकर बात करनी चाहिए।

आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि माता-पिता अपने सभी बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। लेकिन बतौर मनो चिकित्सक, मैं यह कहना चाहती हूं कि कई मामलों में वास्तविकता इससे अलग भी होती है। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स कभी-कभी अपनी जरूरतों या खास परिस्थितियों के कारण किसी एक बच्चे की तरफ ज्यादा झुकाव रख सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे 'माता-पिता का पक्षपात' कहा जाता है।

ऐसा पक्षपात बच्चों के आत्मविश्वास,भावनात्मक विकास और सिबलिंग्स के आपसी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे अपने व्यवहार पर ध्यान दें और सभी बच्चों को समान प्यार, समय और सम्मान देने की कोशिश करें।

आखिर पेरेंट्स क्यों करते हैं पक्षपात?

माता-पिता कई कारणों से किसी एक बच्चे को ज्यादा पसंद कर सकते हैं। इनमें कभी-कभी यह जरूरतों पर निर्भर करता है। जैसे- जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो या भावनात्मक रूप से सहारा देता हो, उसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा सकता है। वहीं, जो बच्चा बीमार हो, कमजोर हो या जिसे ज्यादा देखभाल की जरूरत हो, उसे भी ज्यादा ध्यान मिलता है।

लेकिन हर बार यह झुकाव सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होता। कई बार यह अनजाने में भी हो जाता है।

माता-पिता उस बच्चे के ज्यादा करीब महसूस कर सकते हैं, जिसकी सोच, स्वभाव या रुचियां उनसे मिलती-जुलती हों। इस तरह धीरे-धीरे एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है, जो बिना समझे ही किसी एक बच्चे की तरफ ज्यादा झुकाव पैदा कर सकता है।

इन 3 तरीकों से खुद को संभालें

कब पक्षपात अनजाने में होता है?

ज्यादातर मामलों में माता-पिता जानबूझकर अपने दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यह पक्षपात अक्सर अनजाने में ही होता है और समय के साथ बने मनोवैज्ञानिक पैटर्न से जुड़ा होता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी माता-पिता का बचपन कठिन रहा हो, तो वे अनजाने में एक बच्चे पर ज्यादा ध्यान देकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं।

इसी तरह, कुछ सांस्कृतिक सोच भी इसका असर डालती है, जैसे कुछ जगहों पर बेटों को बेटियों से ज्यादा प्राथमिकता देना।

कब पक्षपात जानबूझकर होता है?

कुछ स्थितियों में माता-पिता किसी एक बच्चे को पक्षपात जानबूझकर भी किया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब माता-पिता भावनात्मक या आर्थिक मदद के लिए किसी एक बच्चे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। इससे परिवार में सही सीमाएं स्पष्ट नहीं रह पातीं और रिश्तों में असंतुलन पैदा हो सकता है।

पेरेंट्स के पक्षपात का बच्चों पर असर

भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है: परिवार में जो बच्चा आज्ञाकारी,खुलकर बोलने वाला या पढ़ाई में अच्छा होता है, उसे अक्सर पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है। वहीं जो बच्चा अंतर्मुखी, जिद्दी या पढ़ाई में कमजोर होता है, उसे कभी-कभी गलत समझ लिया जाता है या उस पर कम ध्यान दिया जाता है।

वहीं, समय के साथ यह स्थिति और मजबूत हो सकती है। 'पसंदीदा' बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता रहता है, जबकि दूसरा बच्चा खुद को अलग महसूस करने लगता है या उसका व्यवहार बदल सकता है। इससे दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है।

खुद पर संदेह बढ़ सकता है: माता-पिता के पक्षपात का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा हो सकता है। जिन बच्चों को कम महत्व मिलता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। वे अक्सर खुद पर शक करने लगते हैं और यह महसूस कर सकते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ऐसी सोच उनके रिश्तों, करियर के फैसलों और मानसिक स्वास्थ्य तक पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

परंपरा तोड़ मैदान में उतरीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलग ही रूप देखने को मिला। आम तौर पर मतदान के दिन सुबह घर पर रहकर हालात पर नजर रखने वाली ममता इस बार परंपरा तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आयीं और खुद बूथ-बूथ जाकर स्थिति का जायजा लिया। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां उनका सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, वहां सुबह से ही ममता बनर्जी की सक्रियता देखने को मिली। कालीघाट स्थित आवास से निकलते ही उन्होंने साफ कर दिया कि आज वह मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। चेतला से शुरुआत करते हुए उन्होंने कई बूथों का दौरा किया, व्यवस्था का जायजा लिया और मतदाताओं से सीधे संवाद किया। इसके बाद पद्मपुकुर रोड होते हुए कई मतदान केंद्रों पर पहुंचकर उन्होंने न केवल व्यवस्था देखी, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से भी बातचीत की।

मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू प्रत्याशी की जीत से सब आश्चर्यचकित

गांधीनगर। गुजरात के गोधरा से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो सामाजिक सौहार्द और जनसमर्थन की एक अनोखी मिसाल बनकर उभरी है। वर्ष 2002 की हिंसा के कारण लंबे समय तक संवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में एक निर्दलीय उम्मीदवार अपेक्सा सोनी ने वार्ड 7 से अप्रत्याशित जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है। यह जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस वार्ड में हिंदू मतदाताओं की संख्या बेहद कम है, फिर भी उन्हें व्यापक समर्थन मिला। वार्ड 7 में सतपुल, हयातनी वाडी, वचला ओधा, चूचला प्लाट, गेनी प्लाट समेत कई इलाके शामिल हैं। यह क्षेत्र गोधरा रेलवे स्टेशन और सिग्नल फालिया से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। हम आपको बता दें कि यही वह स्थान हैं, जिनका संबंध साबरमती एक्सप्रेस आगजनी से जोड़ा जाता है, जिसने 2002 की हिंसा को जन्म दिया था।

सुवेंदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकताओं ने घेरा

कोलकाता। राज्य में विपक्ष के नेता और भाबनीपुर और नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी मतदान के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। उनके दौरे के दौरान, टीएमसी समर्थकों का एक समूह उनके चारों ओर जमा हो गया और जय बंगाल के नारे लगाने लगा। भीड़ ने जल्द ही उन्हें घेर लिया, जिससे मतदान केंद्र पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया। भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। हस्तक्षेप के बाद, भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया और मतदान केंद्र पर सामान्य मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रण में कर लिया गया, जिससे बिना किसी और बाधा के मतदान जारी रह सका।

अभिषेक बनजी के गढ़ डायमंड हार्बर में सिंघम का पहरा

कोलकाता। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का दौरा किया और विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रयागराज में एसीपी के पद पर तैनात हैं। पिछले दो दिनों में डायमंड हार्बर क्षेत्र में डराने-धमकाने और हिंसा रोकने के उनके सक्रिय कदमों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस क्षेत्र को तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कारण 'सिंघम' के नाम से पहचाने जाने वाले शर्मा को मंगलवार को तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपनी भूमिका से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को ''डरा-धमका'' रहे हैं।

वोटिंग के बीच डेरेक ओ ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बुधवार, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने के साथ ही, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए उनसे कहा कि अगर ममता बनर्जी और टीएमसी राज्य में जीतती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। डेरेक ने अपने द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि नरेंद्र, आपने घोषणा की थी कि आप बंगाल की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार हैं। बड़ी-बड़ी बातें करना बंद कीजिए। इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल में जीत हासिल कर लें, तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। राज्य में बुधवार, 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें से अधिकतर तृणमूल के गढ़ हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से प्रभावित हैं। लगभग 32.1 करोड़ मतदाता आज सात जिलों के 142 विधानसभा क्षेत्रों में अपना वोट डालेंगे।

प्रधानमंत्री ने 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर बोले-

सपा विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी: मोदी

हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किमी लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लगभग 36,230 करोड़ रुपए की कुल लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय अभी के 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित 12 प्रमुख जिलों को जोड़ता है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री के हरदोई पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हरदोई से एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ राज्य की विकास यात्रा को नयी गति मिलेगी। उन्होंने छह लेन एक्सप्रेसवे को गांवों, किसानों, उद्यमियों और युवाओं को जोड़ने वाली ''जीवन रेखा'' बताते हुए कहा कि यह विकास को गति देने और दूरियां समेटने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इस परियोजना को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक और राज्य को आधुनिक बुनियादी ढांचे का तोहफा बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे का ये वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं, और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और इस देश की जीवन रेखा रही है वैसे ही

आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेस वे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेस-वे की बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों एक बार फिर देश ने कांग्रेस और सपा का नारी विरोधी चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी, अगर यह संशोधन पास हो जाता तो 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर लखनऊ और दिल्ली पहुंचतीं, वो भी किसी अन्य वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन के खिलाफ वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार मतदान हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं। यह देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है और बड़ी संख्या में मतदान कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है, लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले, जब बिहार में चुनाव हुए तो भाजपा-एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी कल ही गुजरात में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत... इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। 80 से 85 प्रतिशत नगरपालिका और पंचायत भाजपा ने जीत ली हैं। मुझे विश्वास है कि इन पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि ये नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं, और ये आधुनिक हस्तरेखाएं, आज भारत के उज्ज्वल भविष्य का जयघोष कर रही हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि अब वो दौर चला गया, जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थीं। चुनाव के लिए पत्थर लग जाते थे, उसके बाद सरकारें आती-जाती रहती थीं, लेकिन काम का कुछ अता-पता नहीं लगता था। कभी-कभी पुरानी फाइलें ढूंढ़ने के लिए बड़े-बड़े अफसरों को दो-दो साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी होकर रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है। ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के पास असीम क्षमता है, देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है, इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों की हालत खराब है। लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आ रहा है। भीतर बैठे कुछ लोग सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि विकास के नए-नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

चुनाव आयोग ने प्रभावित बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया

कोलकाता। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट, जिसका प्रतिनिधित्व अभिषेक बनर्जी करते हैं, फाल्टा मतदान से पहले एक प्रमुख तनाव का केंद्र बन गई है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और बनर्जी के सहयोगी जहांगीर खान तनाव के केंद्र में रहे हैं, खासकर पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के साथ हुई झड़प के बाद। मतदान के दिन फाल्टा से ईवीएम में खराबी और छेड़छाड़ के नए आरोपों ने आग में घी डाल दिया है। भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने तृणमूल कांग्रेस पर जानबूझकर मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया है, जिससे निर्वाचन क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। सीपीएम और भाजपा दोनों उम्मीदवारों के नामों के बगल में टेप लगाए गए थे। सीपीएम ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। अब, चुनाव आयोग ने ईवीएम पर भाजपा उम्मीदवार का नाम धुंधला किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद प्रभावित बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है और मामले को गंभीर बताया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि यदि इस तरह की और घटनाएं सामने आती हैं, तो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराया जा सकता है। उम्मीदवार के अनुसार, कई मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन पर उनके नाम और पार्टी चिन्ह से संबंधित बटन को कथित तौर पर जाम कर दिया गया था।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली की ग्रेट निकोबार में चल रही 81,000 करोड़ रुपये की सबसे महत्वाकांक्षी रणनीतिक अवसंरचना परियोजना पर निशाना साधते हुए इसे हमारे जीवनकाल में देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे जघन्य अपराधों में से एक बताया। कांग्रेस नेता, जो वर्तमान में द्वीप का दौरा कर रहे हैं, ने कहा कि केंद्र की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विकास की आड़ में विनाश के अलावा कुछ नहीं है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सरकार इसे परियोजना कहती है। मैंने जो देखा है, वह कोई परियोजना नहीं है। यह लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है। यह 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन है जिसे नष्ट होने के लिए अभिशप्त किया गया है। यह उन समुदायों को नजरअंदाज किया गया है जिनके घर छीन लिए गए हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप के जंगलों के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वहां के पेड़ याद से भी पुराने हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जंगल पीढ़ियों से पोषित हुए हैं और द्वीप पर रहने वाले सुंदर

लोगों को उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसे 'परियोजना' कहती है। मैंने जो देखा है, वह कोई परियोजना नहीं है। लाखों पेड़ कटाई के लिए चिह्नित हैं। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन विनाश की कगार पर है। कई समुदायों को नजरअंदाज किया गया है और उनके घर छीन लिए गए हैं। इस विवाद की जड़ में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इस विशाल अवसंरचना परियोजना को दी गई मंजूरी है, जिसे कांग्रेस ने पहले अधूरा और गलत योजना पर आधारित बताया था।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी छोर पर एक माल ढुलाई और रसद केंद्र बनाने की योजना की सोनिया गांधी ने पहले भी आलोचना की थी और केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और स्वदेशी समुदायों का हवाला दिया था।

खेल
प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड ने महिला टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ने पिछले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में खिताबी जीत वाली टीम में शामिल कुल 10 खिलाड़ियों को इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगमी टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है।

न्यूजीलैंड ने बुधवार को स्टार ऑलराउंडर मेली केर को टीम का कप्तान बनाया। इसी के साथ मैजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड टी-20 विश्व कप के लिए अपनी टीम का घोषणा करने वाली दूसरी टीम बन गई। कीवी टीम में अनुभव और युवाओं का अच्छा मेल है, जिसमें अनुभवी सूजी बेट्स और डिवाइन अपने 10वें टी-20 विश्व कप में खेलेंगी, जबकि नई खिलाड़ी नेन्सी पटेल और बल्लेबाज इजी शार्प का आईसीसी टूर्नामेंट में अपने पहले अनुभव के लिए टीम में स्वागत किया गया है। पहली पसंद की स्पिनर ईडन कार्सन अपनी लंबे समय से कोहनी की चोट के कारण टीम में नहीं चुनी जा सकीं।

न्यूजीलैंड के कोच बेन सॉयर ने कहा, %मेरा मानना है कि हमें एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड टीम मिली है जिसमें एक्सपीरियंस और रोमांचक युवा प्रतिभा का मिश्रण है। हमने पिछले 12 महीनों में अपनी बैटिंग डेप्थ को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत की है, खासकर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी हालिया होम सीरीज में इसका फायदा देखने को मिला है।% न्यूजीलैंड टी-20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 में होगा और नॉकआउट स्टेज से पहले इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलेगा।

विश्वकप के लिए न्यूजीलैंड टीम

मेली केर (कप्तान), सूज़ी बेट्स, सोफी डिवाइन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, जेस केर, रोजमेरी मेयर, नेन्सी पटेल, जॉर्जिया प्लिमर, इजी शार्प और ली ताहुहू।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 609 अंक उछला निफ्टी 24177 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत लेते हुए भारतीय शेयर बाजारों ईरान-अमेरिका तनाव के बीच बुधवार (29 अप्रैल) को मजबूती के साथ बंद हुए। तिमाही नतीजों के दम पर ब्लू-चिप शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 77,245 अंक पर खुला। जबकि मंगलवार को यह 76,886 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 77,982 अंक तक चढ़ गया था। अंत में 609.45 अंक या 0.79 फीसदी की बढ़त लेकर 77,496.36 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 24,096 पर खुला और खुलते ही 24,100 के पार चला गया। वहीं, इंट्रा-डे ट्रेड में 77,496. 24,334 अंक के हाई तक चला गया था। अंत में 181.95 अंक या 0.76 फीसदी की बढ़त के साथ 24,177 पर बंद हुआ।

सऊदी अरामको ने रोकी एलपीजी की सप्लाई

नईदिल्ली। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने अपनी एलपीजी शिपमेंट को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। यह कदम फरवरी के अंत में उसकी प्रमुख निर्यात सुविधा जुआयमा को हुए नुकसान के बाद उठाया गया है, जिससे सप्लाई पर असर पड़ा है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने अपने खरीदारों को सूचित किया है कि जुआयमा एलपीजी फैसिलिटी से मई तक शिपमेंट बंद रहेगी। हालांकि, इस संबंध में अरामको की ओर से आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। फरवरी में वेस्ट एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले ही इस फैसिलिटी में एक संरचनात्मक क्षति हुई थी, जिसके बाद से एलपीजी एक्सपोर्ट बंद है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ीं और खरीदारों को वैकल्पिक सप्लाई की तलाश करनी पड़ी।

59 साल बाद ओपेक और ओपेक+ से अलग होगा यूएई

नईदिल्ली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की अस्थिरता के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए ओपेक और ओपेक+ गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया है। 1967 से चला आ रहा यह संबंध अब खत्म होने जा रहा है। 1 मई 2026 से लागू होने वाला यह निर्णय लगभग छह दशक पुराने संबंध के अंत का संकेत देता है और वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मजरूई ने इसे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के अनुरूप सॉवरेन निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम किसी तात्कालिक बाजार उतार-चढ़ाव का परिणाम नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। यूएई 1967 से ओपेक का सदस्य रहा है और तेल बाजार को स्थिर बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

होर्मुज बंद होने से भारत की बढ़ी चिंता

न्यूयॉर्क। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वैश्विक व्यापार के लिहाज से होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही जल्द बहाल करने की अपील की है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के किसी भी तरह के अवरोध का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा और संरक्षण विषय पर आयोजित ओपन डिबेट को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रभारी योजना पटेल ने यह बयान दिया। राजदूत योजना पटेल ने ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना न केवल निंदनीय है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार संतुलन जरूरी?

प्रभु चावला

हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे मायुंग के भारत दौरे से एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने साउथ ब्लॉक में अपनी प्रथागत पूर्व यात्रा ब्रीफिंग आयोजित की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सचिव ने एक असामान्य खुलासा किया : कोरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर के करीब है, पर यह काफी असंतुलित है। हमारा निर्यात करीब 6.5 अरब डॉलर के दायरे में है, जबकि कोरिया का निर्यात करीब 21.4 अरब डॉलर है। इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को पुनर्संतुलित करने की जरूरत है। इसे कूटनीतिक विचलन नहीं मानना चाहिए।

सरकार की ओर से उस सच्चाई का खुलासा किया गया, जिस पर 16 वर्षों से कूटनीतिक चुप्पी थी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के सम्मान में समारोह, सहमति पत्रों और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना, यानी 54 अरब डॉलर करने के वादे को व्यापार असंतुलन की ठोस सच्चाई के बरक्स देखना चाहिए।

दक्षिण कोरिया को भारतीय निर्यात 2021-22 के आठ अरब डॉलर के मुकाबले 2024-25 में गिरकर 5.82 अरब डॉलर रह गया। जबकि इसी दौरान भारत में कोरियाई निर्यात बढ़कर 21.06 अरब डॉलर हो गया। जाहिर है, 2010 में सीईपीए लागू होने के बाद 2024-25 में भारत का व्यापार घाटा लगभग तीन गुना बढ़कर 15.2 अरब डॉलर हो गया। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच कोरिया को भारतीय निर्यात 11 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से कम हुआ, जबकि कोरियाई आयात में सालाना 10 फीसदी की वृद्धि हुई। द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य नया नहीं है। वर्ष

2019 में भी यही लक्ष्य रखा था। नई बात यह है कि भारत ने स्वीकार किया है कि व्यापार असंतुलन को सुधारे बिना 50 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने से भारत का व्यापार घाटा और बढ़ेगा। भारतीय क्षोभ के केंद्र में वे कोरियाई ब्लूचिप सब्सिडीयरी हैं, जिनका भारतीय परिचालन मूल्य और नकदी पैदा करने की शक्ति मूल कोरियाई कंपनियों की तुलना में बहुत अधिक है।

इस प्रसंग में सबसे कष्टप्रद आयाम 'वियतनाम विरोधाभास' है। वर्ष 2024 तक भारत में कोरिया का संचयी एफडीआई लगभग 10 अरब डॉलर था। बावजूद इसके कि भारतीय अर्थव्यवस्था वियतनाम की अर्थव्यस्था से 10 गुना बड़ी है, उच्च रॉयल्टी, आईपीओ कैश-आउट और लाभांश प्रवाह के माध्यम से कोरियाई कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं से अर्जित मुनाफे से वियतनामी कारखानों को सब्सिडी दे रही हैं, जो फिर तैयार माल भारत निर्यात करते हैं। क्यों?

स्वदेशी नेता यह सवाल पूछते हैं कि क्या कोरियाई समूहों को भारत से निकाली गई नगदी को एक छोटे पड़ोसी देश में विनिर्माण सुविधाओं में निवेश करना चाहिए, जो फिर भारतीय उद्योग को ही कमजोर करता है? यह बेहद क्षुब्ध करने वाली स्थिति है कि भारत को एक दुधारू गाय समझ लिया गया है। यह आत्मनिर्भरता के भारतीय विमर्श की आत्मा पर प्रहार है।

दूसरी ओर, भारतीय फर्में उच्च अनुपालन लागत, विलंबित अनुमोदन और रॉयल्टी के बोझ से जूझ रही हैं, जो स्थानीय नवाचार को भूखा रखता है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद सीईपीए को अपग्रेड करने की बात होने के साथ-साथ हिसाब-किताब करने का समय आ गया है।

इसके बावजूद यह मौलिक प्रश्न बना हुआ है: क्या दिल्ली नियमों को फिर से लिखने का साहस जुटा पाएगी, या कोरियाई या जापानी प्रभाव एक बार फिर उस यथास्थिति को बनाए रखेगा, जो भारत की औद्योगिक संप्रभुता को खत्म करते हुए संपत्ति निकालती है? इस प्रश्न का उत्तर न केवल भारत-कोरिया व्यापार संबंधों के भविष्य को परिभाषित करेगा, बल्कि भारत द्वारा हस्ताक्षरित हर रणनीतिक साझेदारी की विश्वसनीयता भी तय करेगा। भारत के पास वह प्रभाव है, जिसका उसने पहले कभी उपयोग नहीं किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई डिजिटल सेवा का शुभारंभ

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा आमजन तक प्रभावशाली, पारदर्शी और डिजिटल नागरिक सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के उन्नत संस्करण 'सेवा सेतु' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रीद्वय अरुण साव और विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डिजिटल नागरिक सेवाएं और अधिक सशक्त और प्रभावी होंगी। वर्ष 2003 में प्रारंभ हुए चॉइस मॉडल से लेकर वर्ष 2015 के ई-डिस्ट्रिक्ट और अब 'सेवा सेतु' तक छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में एक लंबी और उल्लेखनीय यात्रा तय की है तथा यह प्लेटफॉर्म अब नागरिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बन चुका है, जिससे लाखों नागरिकों को लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'सेवा सेतु' के माध्यम से अब एक ही पोर्टल पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाओं की जानकारी सहज रूप से प्राप्त की जा सकेगी। आय, जाति, निवास, राशन कार्ड और विवाह पंजीयन जैसे प्रमुख प्रमाण-पत्रों सहित अब तक 3.2 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं और इतने ही प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 30 से अधिक विभागों के एकीकरण के साथ यह

प्लेटफॉर्म एक सशक्त ÷वन स्टॉप सॉल्यूशन÷ के रूप में विकसित हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'सेवा सेतु' राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई मजबूती प्रदान करेगा।

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का संचालन राज्य स्तर पर चिप्स द्वारा किया जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। नई प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधार, व्हाट्सएप और 'भाषिणी' जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकृत उपयोग किया गया है, जिससे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, सेवा की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजी लॉकर, ई-प्रमाण और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण कर सेवाओं को और अधिक सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाया गया है। 'सेवा सेतु' में ट्रेजरी और ई-चालान का एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे तथा डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से संभव होगी। पोर्टल में क्यूआर कोड आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल सिग्नेचर, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं तथा यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवाओं की समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेशन, समय-सीमा संकेतक और स्वतः शिकायत पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी। राज्य में सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से अधिक चॉइस सेंटर और 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय हैं, जहां से नागरिक आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। 'सेवा सेतु' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनसेवा के केंद्र में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से बाधारहित बनाया गया है, जिससे शासन और नागरिकों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है और सेवाएं सीधे नागरिकों के हाथों तक पहुंच रही हैं।व्हाट्सएप इंटरफेस के माध्यम से नागरिक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे, पावती रसीद और दस्तावेजों के लिंक तुरंत प्राप्त कर सकेंगे तथा अनुमोदन के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे।

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान में डॉ. भीष्मदेव साहू को डॉ सी एम सिंह नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड

रायपुर। सरगुजा जिले के पशु चिकित्सालय मंगारी प्रभारी एवं अनुभवी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. भीष्मदेव साहू को पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान डॉ. सी एम सिंह एक्सीलेंस अवार्ड इन वेटरनरी साइंसेस - 2026 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिये देश और विदेश के 8 संस्थान के द्वारा मूल्यांकन किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से पूरे प्रदेश, विशेषकर जिला बालोद, सरगुजा, उतई नगर एवं साहू समाज में हर्ष और गर्व का माहौल है। इस उपलब्धि के लिए पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

डॉ. साहू वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के पशु चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित उप संचालक कार्यालय से संबद्ध हैं और विकासखंड बतौली के मंगारी पशु चिकित्सालय प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग 15 वर्षों से राज्य शासन में पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में कार्यरत हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संगम डॉ. साहू ने अपने कार्यकाल में पशु चिकित्सा सेवा, जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके पास मजबूत फील्ड अनुभव के साथ-साथ गहन अनुसंधान पृष्ठभूमि भी है। पशु कल्याण, निदान, चिकित्सा और आधुनिक उपचार पद्धतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। उन्होंने पशु रोग (लम्पी स्किन डिजीज, थनौती), कृत्रिम गर्भधान विषय पर राज्य और जिला स्तर पर पशु चिकित्सक, क्षेत्र अधिकारी और सहयोगियों को ट्रेनिंग प्रदान किये।

जनगणना 2027: कान सूचीकरण एवं गणना कार्य हेतु व्यापक तैयारियां

रायपुर। राष्ट्रीय महत्व का व्यापक अभियान जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य 01 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस संबंध में तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों एवं प्रमुख जनगणना अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का व्यापक अभियान है, जिसके माध्यम से देश की जनसंख्या, आवासीय स्थिति एवं सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का सटीक आकलन किया जाता है, तथा मकान सूचीकरण एवं गणना इसकी आधारशिला है।

प्रशिक्षण एवं फील्ड कार्य पर विशेष जोर जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने निर्देशित किया कि सभी जिलों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। फील्ड कार्य के दौरान डेटा संग्रहण की विधि, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा संभावित चुनौतियों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी क्षेत्र गणना कार्य से न छूटे और न ही किसी क्षेत्र का दोहराव हो।बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी किए जाएं, ताकि आम नागरिकों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों एवं उनसे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बड़ी आवासीय कॉलोनियों एवं अपार्टमेंट्स में जनगणना कार्य के सुचारू संचालन हेतु आवासीय कल्याण समितियों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर भी बल दिया गया। डिजिटल डेटा संग्रहण एवं गुणवत्ता पर जोर जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कहा कि इस बार जनगणना के आंकड़े मोबाइल एप के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं, अत: प्रत्येक प्रविष्टि को अत्यंत सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाए।

आईपीएस संतोष सिंह ने संभाला सीआईएसएफ दक्षिण जोन-2 के डीआईजी का पद

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह ने हैदराबाद स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दक्षिण जोन-2 के उप महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके इस नए दायित्व के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक में स्थित सीआईएसएफ द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण संस्थानों और इकाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शामिल है। बताया गया है कि दक्षिण जोन-2 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां, खनन क्षेत्र, बड़े कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य रणनीतिक प्रतिष्ठान आते हैं, जिनकी सुरक्षा का दायित्व अब संतोष सिंह के नेतृत्व में रहेगा। इसके साथ ही बंगाल और ओडिशा के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी इसी जोन के अंतर्गत आती है।

जो इस पद की जिम्मेदारियों को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। संतोष सिंह के कार्यभार संभालने के साथ ही जोन में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं। सीआईएसएफ देश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बल है। ऐसे में दक्षिण जोन-2 जैसे बड़े क्षेत्र का नेतृत्व संभालना एक अहम प्रशासनिक दायित्व माना जाता है।

सूत्रों के अनुसार संतोष सिंह इससे पहले भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्हें सुरक्षा प्रबंधन का अच्छा अनुभव है। उनके नेतृत्व में जोन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति से संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा समन्वय और निगरानी को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न राज्यों के प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस नियुक्ति को छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य के अधिकारियों की केंद्रीय स्तर पर भागीदारी और जिम्मेदारी में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनायें रुक नहीं रही है: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अंबिकापुर के सीतापुर में दो नाबालिक बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। घटना 24 अप्रैल के रात की है, 4 बच्चियां शादी से आ रही थी 9 बदमाश उनको रास्ते में रोक कर गैंगरेप किया। यह बच्चियां विशेष पिछड़ी जनजाति की है। प्रदेश में महिलाओं, मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनायें रुक नहीं रही

है। जशपुर, रायगढ़, कवर्धा, बालोद सभी जगहों पर आदिवासी बच्चियों के साथ दुराचार की घटनायें हुई है। यह घटनायें विचलित करने वाली और शर्मनाक है। प्रदेश में महिलायें सुरक्षित नहीं है, सरकार महिलाओं, बच्चियों को सुरक्षित वातावरण दे पाने में असफल साबित हो रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के प्रशासन में छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 8 से 9 महिलाएं दुराचार के शिकार हो रही है, हर दूसरे दिन सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है, सरकारी आश्रम स्कूलों में नाबालिक बच्चियों गर्भवती हो रही है, जब पीड़िता थाने जाते हैं तो एफआईआर करके आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ितों को ही प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। साय सरकार में प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हो गई है।

मितानिनों के पास मरीजों को देने जरूरी दवाई नहीं: ठाकुर

रायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली कड़ी मितानिनों को बीते कई माह से 22 प्रकार की दवाई नहीं मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में प्राथमिक स्वास्थ्य की पहली कड़ी मितानिनों को बीते कई माह से जरूरी दवाईयां

उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। बस्तर सम्भाग सहित प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में एक-एक मितानिनों पर 30 से 40 घरों की प्राथमिक ईलाज की जिम्मेदरीं है लेकिन जरूरी दवाई नहीं होने के कारण मरीजो को निजी ईलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। मितानिनों को ट्रेनिंग के दौरान गर्भवती महिला का देखभाल, संस्थागत प्रसव, सर्प दंश के लिए अस्पताल ले जाना, सर्दी, बुखार, दर्द, पेट दर्द, उल्टी दस्त, एलर्जी का ईलाज, करने की ट्रेनिंग दी गई है। ईलाज के लिये सर्दी, बुखार, पेट दर्द की दवा, ओआरएस घोल, मल्टी विटामिन टेबलेट, घाव एवं एलर्जी के लिये, एंटीसेप्टिक क्रीम, बीटाडीन, डिटॉल साल्यूशन, लोशन सहित 22 प्रकार की दवाई दी जाती है, लेकिन दवा नहीं होने के चलते मितानिन ईलाज नहीं कर पा रहे है।

पुलिस भेज कर व्यवसायियों को डरा रही है सरकार : वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दवा दुकानों की जांच के लिए खाद्य और औषधि विभाग के साथ पुलिस और राजस्व अमला भेजने के सरकारी आदेश पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार ने आदेश निकाला है कि अब मेडिकल स्टोरों की जाँच खाद और औषधि विभाग के इंस्पेक्टर के साथ पुलिस

और राजस्व अमला भी करेगा। मेडिकल स्टोर में जांच के लिए पुलिस लेकर एसडीएम, तहसीलदार भी जा रहे है। सरकार के पास ऐसा क्या इनपुट मिला है जो यह कार्यवाही की जा रही यह तो आपात स्थिति में होता है कि पुलिस जांच के लिए जाए। यह निर्णय गलत है सरकार को अपने औषधि विभाग के लोगों पर भरोसा नहीं। पुलिस और राजस्व क्यों जाँच करेगा? कहीं गड़बड़ी है तो पुलिस स्वमेव जाँच कर सकती है लेकिन हर रोज पुलिस दुकान की जाँच करने पहुंचेगी तो इससे दुकानदार की परेशानी बढ़ेगी। राज्य में नकली दवा तो सरकारी अस्पतालो और मेडिकल सप्लाई कारपोरेश के पास पकड़ा रही जांच निजी मेडिकल का करेंगे। कांग्रेस, सरकार के निर्णय का विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार में प्रशासनिक आतंक चरम पर है।

हेलमेट नियम सख्त, पीछे बैठने वालों के लिए भी अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के तहत सख्त प्रवर्तन के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि चार वर्ष से अधिक आयु के सभी सवारों पर यह नियम लागू होगा। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, अतिरिक्त आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर दोपहिया वाहन पर सवार हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यह प्रावधान मोटरयान अधिनियम की धारा 129 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। उन्होंने कहा कि यह नियम केवल चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों पर भी समान रूप से लागू होता है। उन्होंने बताया कि हेलमेट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन रक्षक उपकरण है, जो दुर्घटना की स्थिति में सिर की गंभीर चोटों से बचाव करता है। इसके लिए हेलमेट का सही तरीके से पहना और बांधा जाना भी जरूरी है। हालांकि कानून में कुछ सीमित छूट भी दी गई है, जैसे पगड़ी पहनने वाले सिखों के लिए विशेष प्रावधान है, जबकि चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अलग सुरक्षा उपाय तय किए जा सकते हैं।

204 खिलाड़ियों का किया गया कौशल परीक्षण

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए आज रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में तीरंदाजी, फुटबॉल और वेटलिफ्टिंग के 204 खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया गया। आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों का चयन मोटर एबिलिटी एवं खेल कौशल के आधार पर किया जाता है।चयन ट्रायल के तीसरे दिन 30 अप्रैल को हॉकी और एथलेटिक्स अकादमी में चयन के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल और दक्षता परीक्षण किया जाएगा। अगले दिन 1 मई को मापदंडों पर खरे उतरने वाले खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आवास, भोजन व मेडिकल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

तकनीक आधारित प्रचार ऐप से होगी आउटडोर मीडिया मॉनिटरिंग

रायपुर। सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और नई पहलों के प्रचार-प्रसार में आउटडोर मीडिया एक अत्यंत प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित है। इसमें होर्डिंग्स, यूनिपोल्स, ब्रांडिंग, डिजिटल वॉल पेंटिंग्स और एलईडी वैन अभियान शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, बस स्टॉप्स तथा प्रमुख यातायात मार्गों जैसे उच्च आवागमन वाले स्थानों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से अधिक होता है। जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने पैनल में शामिल सभी एजेंसियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने आउटडोर मीडिया की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तकनीक आधारित प्रचार ऐप समाधान अपनाने पर विशेष जोर दिया।

नई प्रणाली 01 अप्रैल 2026 से होर्डिंग्स और यूनिपोल्स के लिए लागू की जा चुकी है और जल्द ही इसे एलईडी स्क्रीन, ब्रांडिंग तथा डिजिटल वॉल पेंटिंग्स जैसे अन्य प्रारूपों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह प्रिंटिंग पर काफी शिकायतें सामने आ रही थीं, इन शिकायतों के कारण टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। नई प्रिंटिंग पॉलिसी यथा-शीघ्र लागू की जावेगी। इस हेतु बेहतर एवं पारदर्शी पॉलिसी लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों की मुद्रण नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है।

आउटडोर मीडिया के क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग एक बड़ी चुनौती रही है। कई मामलों में यह शिकायतें सामने आई हैं कि वेंडर्स द्वारा सरकारी विज्ञापनों की स्थापना में देरी की गई या निगरानी के अभाव में उन्हें समय से पहले हटाकर उनकी जगह व्यावसायिक विज्ञापन लगा दिए गए। इस समस्या के समाधान के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम प्रचार ऐप विकसित किया गया है।

यह प्रणाली तीन चरणों में कार्य करती है। पहले चरण में विभाग प्रचार अभियान की योजना बनाती है, पैनल में शामिल एजेंसियों और उनके एसेट्स का चयन कर प्रचार अभियान कार्य आवंटित करती है। दूसरे चरण में वेंडर्स प्रचार अभियान की समीक्षा कर क्रियान्वयन की योजना बनाती है और एसेट्स को माउंटर्स को सौंपती है। तीसरे चरण में माउंटर्स मैदानी स्तर पर निर्धारित स्थानों पर क्रिएटिव सामग्री स्थापित करती है। रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए माउंटर्स हेतु एक एंड्रॉइड ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से माउंटर्स को जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो तीन चरणों में अपलोड करना अनिवार्य किया गया है-स्थापना से पहले, स्थापना के तुरंत बाद, और अभियान अवधि के दौरान प्रतिदिन कम से कम एक बार। इन तस्वीरों की पहले वेंडर एजेंसी द्वारा समीक्षा की जाती है और फिर उन्हें ऑनलाइन विभाग को भेजा जाता है। यह एंड-टू-एंड प्रणाली पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है और विभाग को सभी सक्रिय अभियानों की लगभग वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराती है। इससे प्रत्येक आउटडोर एसेट की अलग-अलग ट्रैकिंग संभव हो पाती है और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

आप पर बोले भूपेश बघेल, लेकिन भाजपा पर खामोशी क्यों: उत्तम जायसवाल

रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब भाजपा की टीम-B की भूमिका निभाती नजर आ रही है। भाजपा सरकार ने प्रदेश को विनाश की ओर धकेल दिया है, लेकिन कांग्रेस जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खामोश है। दलबदल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा कि भूपेश बघेल आम आदमी पार्टी पर तो हमला बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर पूरी तरह खामोश हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताना कांग्रेस की राजनीतिक बेचैनी और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति को दर्शाता है।

जायसवाल ने सवाल किया, यदि भूपेश बघेल आम आदमी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें भाजपा की भूमिका पर भी स्पष्ट बोलना चाहिए।क्कपर आरोप लगाने में कांग्रेस इतनी तत्परता दिखाती है, लेकिन भाजपा के खिलाफ उसकी आवाज कमजोर क्यों पड़ जाती है? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, युवाओं के भविष्य और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े सवालों पर जवाब चाहती है। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने के बजाय आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। यह साफ दिखाता है कि कांग्रेस वास्तविक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल हो चुकी है।जायसवाल ने कहा कि यदि कांग्रेस सचमुच भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, तो उसे भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, प्रशासनिक विफलताओं और जनता की परेशानियों पर मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वह भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देश में ईमानदार और काम की राजनीति का मजबूत विकल्प बनकर उभरी है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.